www.tamsasanket.com
वर्षः 06 || अंक 135 || लखनऊ
शुक्रवार
14 अगस्त 2026 || पृष्ठः 04 || मूल्यः ₹2
आज़ादी का अमृत महोत्सव
https://epaper.tamsasanket.com
दैनिक
तमसा संकेत
लखनऊ व अम्बेडकर नगर से एक साथ प्रकाशित
» डॉ. लोहिया की जन्म भूमि से सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र

मौसम
सूर्योदयः 05:37
सूर्यास्तः 06:44
अधिकतमः 32°00
न्यूनतमः 28°00



पेज 07

विशेष समाचार | विदेशी चंदे पर नियंत्रण और... >>पेज 04 | मुरादाबाद में हाईवे पर बिछे... >>पेज 06 | लोग मुझे क्राइम पेट्रोल के लिए याद...

मोदी-शाह और राहुल सदन में मौजूद रहे, बंदर के खिलौने के साथ विपक्ष का प्रदर्शन

लोकसभा 1 मिनट-राज्यसभा 1 घंटे चली, संसद सत्र खत्म



केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मानसून सत्र चर्चा की नजर से अच्छा नहीं रहा। पहली बार ऐसा देखा गया है, जब सरकार संसद में चर्चा चाहती है और विपक्ष बहस से भाग रहा है। सभापति राधाकृष्णन ने कहा- छुआछूत जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। यह पाप है। हम सभी शुद्ध हैं। मामले की जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी चाहिए।



लोकसभा में 114 घंटे में से 96 घंटे काम नहीं हुआ

मानसून सत्र में लोकसभा की 19 बैठकें हुईं। सदन की सामान्य बैठक सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक होती है। दोपहर 1 से 2 बजे तक लंच ब्रेक रहता है। यानी एक दिन में करीब 6 घंटे कार्यवाही का समय होता है। इस हिसाब से 19 बैठकों में करीब 114 घंटे कार्यवाही होनी थी, लेकिन यह करीब 17 घंटे 30 मिनट ही चली। यानी करीब 96 घंटे 30 मिनट कम कार्यवाही हुई। वहीं, 2025 का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त 2025 तक चला था। इसमें लोकसभा और राज्यसभा की 21-21 बैठकें हुईं। लोकसभा में सिर्फ 37 घंटे काम हुआ था।

एअर इंडिया पायलट्स का अब रोज ड्रग टेस्ट होगा

फुकेट-दिल्ली फ्लाइट हादसे के बाद फैसला

जानकारी

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस के सभी पायलटों की अब रोज जांच होगी कि उन्होंने प्रतिबंधित दवाओं या नशीले पदार्थों का नशा तो नहीं किया है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। यह टेस्ट आज से अनिवार्य कर दिया गया है। दोनों एयरलाइंस में 5 हजार से ज्यादा पायलट हैं। पिछले हफ्ते फुकेट-दिल्ली फ्लाइट के एक पायलट का ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद यह फैसला लिया गया। दरअसल, इस फ्लाइट के भुवनेश्वर से गुजरते समय



अचानक टर्बुलेंस जैसे हालात बने और यह करीब 300 फीट नीचे आ गई थी। जिससे यात्रियों और क्रू मेंबर्स को चोटें आई थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस घटना के बाद पायलट (कैप्टन) के दो ड्रग्स टेस्ट हुए थे। दोनों टेस्ट पॉजिटिव थे। दूसरे में गांजा पीने की पुष्टि हुई थी। फ्लाइट के पैसेंजर ने आरोप लगाया था कि पायलट नशे में था।

आरोप

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र गुरुवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 1 मिनट चली, जबकि राज्यसभा करीब 1 घंटे चली। लोकसभा में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पूरी कैबिनेट और विपक्ष के नेता राहुल गांधी मौजूद रहे। स्पीकर ओम बिड़ला ने वंदे मातरम गान के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। वहीं, राज्यसभा में आखिरी दिन MMDR संशोधन बिल पास हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी में उनके कार्यक्रम के बाद हुए शुद्धिकरण का मुद्दा उठाया। इधर, विपक्षी सांसद संसद के बाहर बंदर का खिलोना लेकर पहुंचे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।

>> (शेष पेज 06 पर)

मानसून सत्र में 12 नए बिल पेश, 11 दोनों सदनों में पास

2026 के मानसून सत्र में कुल 12 नए बिल पेश किए गए। इनमें 10 लोकसभा और 2 राज्यसभा में पेश हुए। लोकसभा में आए बिल टैक्स, बैंकिंग, खनन, ट्रिब्यूनल, जन्म-मृत्यु पंजीकरण, परीक्षा में नकल रोकने, केरल का नाम बदलने और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या जैसे मुद्दों से जुड़े हैं। माइंस एंड मिनरल्स संशोधन बिल के राज्यसभा से पास होने के बाद अब 12 में से 11 बिल दोनों सदनों से पास हो चुके हैं। केवल भारतीय सांख्यिकी संस्थान बिल अभी दोनों सदनों से पास नहीं हुआ है।

खड़गे ने कहा- हल्द्वानी में मेरे जाने के बाद स्टेज का शुद्धिकरण किया

राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा- 'मैं हल्द्वानी में था, जहां मैंने रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया। वहां लाखों लोग मौजूद थे। उस समय मैंने किसी समुदाय या धर्म का नाम नहीं लिया।





विपक्षी सांसद मंकी टॉय लेकर संसद परिसर में पहुंचे और नारे लगाए।



मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया। प्रियंका गांधी और सुप्रिया सुले समेत अन्य सांसद मौजूद थे।

लोकसभा में गुरुवार को कार्यवाही शुरू होते ही वंदे मातरम का गान हुआ। इसके बाद कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।

शाह ने जंतर-मंतर प्रदर्शन पर चर्चा के लिए स्पीकर को लेटर लिखा

गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को जंतर-मंतर प्रदर्शन पर संसद में चर्चा की पेशकश करते हुए स्पीकर को पत्र लिखा है। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष को शाह का "लेक्चर" नहीं चाहिए, पहले बताएं कि छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'मैं पूरी तरह निराश हूं। सरकार चर्चा चाहती है, लेकिन विपक्ष भाग रहा है।' उन्होंने कहा कि विपक्ष तैयार हो तो सत्र बढ़ाया जा सकता है।

नड्डा बोले- भाजपा हल्द्वानी शुद्धिकरण की घटना का समर्थन नहीं करती

राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, 'खड़गे जी ने जो कहा, वह बेहद दुखद है। यह सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए दुख की बात है। बीजेपी ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती। कभी नहीं। लेकिन हम इसकी जांच करेंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि वहां जो कुछ हुआ, उसकी निश्चित रूप से जांच की जाएगी।' मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि बीजेपी ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती। मैं इसकी निंदा करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मामले को देखेंगे। यह हम सभी के लिए बेहद अफसोस की बात है कि आपकी भावनाएं आहत हुईं।

यूपी में सपा सरकार बनी तो आजम खान बनेंगे गृहमंत्री!

शिवपाल यादव ने रामपुर में किया ऐलान

मुलाकात

तमसा संकेत, एजेंसी



लखनऊ। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा और विधायक शिवपाल सिंह यादव गुरूवार को जेल में बंद पूर्व मंत्री आजम खान से मिलने पहुंचे। शिवपाल ने करीबन एक घंटे उनसे जेल में मुलाकात की। बाहर आने के बाद शिवपाल ने मीडिया से कहा कि इस बार सपा सरकार में आजम खान को गृह मंत्री बनाया जाएगा। शिवपाल ने आजम खान की पत्नी पूर्व सांसद तंजीन फातिमा और बड़े बेटे अदीब आजम से मिले। इसके

शिवपाल सिंह यादव ने रामपुर में आजम खान से जेल में मुलाकात की। इसके बाद मीडिया के सामने घोषणा की कि वे आजम को गृह मंत्री बनाएंगे।

बाद शिवपाल जौहर यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से मिले और उनके साथ बैठक में समस्या को सुना।

>> (शेष पेज 06 पर)

फास्ट न्यूज

पंजाब के पूर्व डिप्टी-सीएम सुखबीर बादल पर गुरुद्वारे में हमला

लुधियाना/महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरुवार को शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हमला हुआ। पुलिस के मुताबिक, गुरुद्वारा माता साहिब कौर में एक निहंग ने उन पर कृपाण से हमला किया। बादल के हाथ में चोट लगी है।

डायन बताकर हत्या जैसी कुप्रथाएं रहीं तो लोकतंत्र नहीं टिकेगा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डायन बताकर हिंसा जैसी कुप्रथाएं कानून के राज और संवैधानिक नैतिकता से बचती रहेंगी तो संवैधानिक लोकतंत्र नहीं टिक सकता। कोर्ट ने ओडिशा में 1998 में एक महिला को डायन बताकर घर से बाहर खींचने और पीटने वाले व्यक्ति की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी। इस हमले में महिला की मौत हो गई थी। आरोपी ने एक अन्य आरोपी के साथ मिलकर महिला पर हमला किया था। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने यह फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि इस मामले में महिला की बेटी ने अपनी मां को बेहद क्रूर तरीके से मारे जाते देखा था।

हरियाणा-जीटी रोड पर ही लंगर चलाने की तैयारी

अंबाला। हरियाणा के अंबाला में पुलिस और सिख संगत के बीच गुरुवार दोपहर में शुरू हुआ टकराव देर शाम तक शांत नहीं हुआ। दोपहर करीब 2 बजे के बाद से जीटी रोड (NH-44) पर अंबाला जग्गी सिटी सेंटर के बाहर जाम लगाया हुआ है। ट्रैफिक को शाहाबाद की ओर से डायवर्ट किया गया है। अंबाला रेंज के आईजी पंकज नैन और एसपी अजीत शेखावत लोगों को समझाने भी आए।

गुटखा-तंबाकू पर सरकार ने 1 साल के लिए लगाया बैन

खरीदना-बेचना और बनाना सब पर प्रतिबंध

रोक

तमसा संकेत, एजेंसी

बेंगलुरु। अगर आप गुटखा-तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं या इसके कारोबार से जुड़े हैं. तो यकीन मानें यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. राज्य सरकार ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू-निकोटीन वाले उत्पादों पर एक साल की रोक लगा दी है. यह प्रतिबंध सिर्फ बिक्री पर नहीं है. इसके साथ ही यह बैन बनाने में, स्टोर करने में, सामान को इधर से उधर भेजने-पहुंचाने में भी



सामान कहां बना, कहां रखा गया और किस रास्ते से बाजार तक पहुंचा, इसकी भी जानकारी जुटाई जा सकती है. खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को ऐसे उत्पादों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं. विभाग का कहना है कि प्रतिबंधित उत्पादों का सर्कुलेशन रोकने के लिए नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा।

लागू रहेगा. जिसके बाद पूरे राज्य में जांच अभियान तेज कर दिया गया है. तो आइए बिना देर समझते हैं क्या है मामला. किन उत्पादों पर रोक है और इसका असर किस पर पड़ेगा, समझिए पूरी कहानी. मामला कर्नाटक का है.

>> (शेष पेज 06 पर)

हमारा काम आवाज बुलंद करना, सरकार को समझ आ गया कि लोग अब चुप नहीं रहेंगे

देश में लोगों को बोलने से रोका जा रहा : राहुल

आरोप

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि सरकार लोगों को अपनी बात रखने से रोक रही है। सरकार व्यवस्था लागू करना चाहती है, जबकि कांग्रेस का काम भारत को अपनी बात कहने का मौका देना है। दिल्ली में हो रहे कांग्रेस का 'रचनात्मक कांग्रेस प्रकोष्ठ' के अधिवेशन में राहुल ने कहा कि जंतर-मंतर पर छात्र अपनी बात रखना चाहते थे।



दो दिन के अधिवेशन में कई मुद्दों पर चर्चा

रचनात्मक कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन 12 अगस्त को नई दिल्ली के इंदिरा भवन में शुरू हुआ था। इसमें सामाजिक संगठनों, कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, अकादमिक जगत, कलाकारों, समुदाय प्रतिनिधियों और नागरिक समाज से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। पहले दिन अर्थव्यवस्था, रोजगार, गरीबी और असमानता, पर्यावरण, विकास, विस्थापन, प्रदूषण, स्वास्थ्य, न्याय, अधिकार, संस्कृति और शोध जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

पहली बार अभिव्यक्ति का सामना करना पड़ रहा

- राहुल गांधी ने कहा कि उनकी कोशिशें सरकार को परेशान कर सकती हैं। उन्होंने दावा किया कि PM मोदी रात में सो नहीं पाते।
- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कभी चाणक्य और सरदार पटेल जैसे नामों से जोड़ा जाता था, लेकिन अब वह संसद में प्रवेश तक नहीं कर पाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहली बार उन्हें भारत की आवाज और उसकी अभिव्यक्ति का सामना करना पड़ रहा है।
- भारत में बहुत से लोग कायरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। अगर आप ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ रहे हों और डर लगने की बात कहें तो समझ में आती है, लेकिन आज आप उन मसखरों और जोकरों से लड़ रहे हैं, जिन्हें हमारे दर्शन या इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है।
- यदि किसी दिन आरएसएस की अभिव्यक्ति को खत्म करने की बात होगी तो वह उसकी भी रक्षा करेंगे।

बैठक : छह अंतरे बजने के बाद सदन स्थगित, राज्यसभा में भी यही हुआ

लोकसभा की कार्यवाही पहली बार वंदे मातरम से शुरू हुई

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। लोकसभा की मानसून सत्र की आखिरी बैठक गुरुवार को पहली बार वंदे मातरम् से शुरू हुई। इस दौरान पीएम मोदी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पूरा सदन मौजूद था। राष्ट्रगीत के छह अंतरे बजाए गए। इसके बाद लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और मानसून सत्र खत्म हो गया। राज्यसभा भी राष्ट्रगीत के साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई इसके पहले विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने हल्द्वानी के



रामलीला मैदान में कथित 'शुद्धिकरण' का मुद्दा उठाया। यह कार्यक्रम 8 अगस्त 2026 को वहां कांग्रेस अध्यक्ष की रैली के बाद किया गया था।

प्रियंका ने कहा- गृह मंत्री आज वंदे मातरम गाने आए थे

- प्रियंका गांधी ने कहा, 'गृह मंत्री आज आए, लेकिन सिर्फ वंदे मातरम गाने। पूरा सत्र बीत गया, लेकिन न तो प्रधानमंत्री और न ही गृह मंत्री सदन में उपस्थित रहे। ऐसे में ये लोकतंत्र और संसद कैसे चल सकती है?'
- समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने पूरे वंदे मातरम् के गायन को लेकर सवाल उठाए हुए। उन्होंने कहा, 'जिन लोगों ने इसके संबंध में कानून बनाया है, उन्हें भी पूरा राष्ट्रगीत याद नहीं है। पहले जितना वंदे मातरम् गाया जाता था, वह सभी को याद रहता था, लेकिन अब पूरा गीत याद रखना मुश्किल है।



वंदे मातरम बिल 11 अगस्त को कानून बना

राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' को राष्ट्रगान के समान कानूनी दर्जा देने वाला राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) बिल, 2026 राज्यसभा से 29 जुलाई और लोकसभा से 30 जुलाई 2026 को पास हुआ था। इसके बाद 11 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया।

यूपी की महिलाओं को 40 हजार देंगे : अखिलेश यादव

भाजपा की पाप की कमाई, यूपी की महिलाएं कभी नहीं लेंगी

आरोप

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश की महिलाओं को 20 हजार रुपए देने की भाजपा सरकार की योजना पर हमला बोला है। उन्होंने कहा- भाजपा की ये कमाई पाप की है। जिसे यूपी की धर्मभीरू महिलाएं कभी नहीं लेंगी। इसे भाजपा का एक और जुमला बताते हुए आरोप लगाया कि भाजपा के पास चुनाव जीतने के लिए पैसे के सिवा कुछ नहीं बचा है। अखिलेश ने दोहराया कि सपा सरकार बनने पर महिलाओं को 40 हजार रुपए दे कर शुरुआत की जाएगी।

>> (शेष पेज 06 पर)



अखिलेश ने एक्स पर लिखा- भाजपा का एक और जुमला यूपी की महिलाओं को 20000 देंगे। भाजपा की यह कमाई 'पाप की कमाई' है, जिसे धर्मभीरु महिलाएं कभी नहीं लेंगी। सपा प्रमुख ने दावा किया कि दूसरे राज्यों में महिलाओं को पैसे देने की घोषणा कर चुनाव जीतने वाली भाजपा सरकारें अब पैसे देने से आनाकानी कर रही हैं।

योगी सरकार स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) पर सभी जिलों में कराएगी स्थापना, लगेंगे 'एक पेड़ मां के नाम'

पर्यावरण संरक्षण के साथ ही राष्ट्रभक्ति का भी संदेश देगी 'वंदे मातरम वाटिका'

भागीदारी

- लखनऊ के कुकरैल में भी वाटिका का होगा विस्तार, अशोक चक्र की 24 तीलियों के बाहरी तरफ लगाए जाएंगे अशोक के पौधे
- जनसहभागिता से होगा आयोजन, भारतीय वन सेवा के वर्तमान/पूर्व अधिकारी, विद्यार्थी, स्वयंसेवी संस्थाएं व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों की रहेगी भागीदारी



तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। योगी सरकार के मार्गदर्शन में वन विभाग विशिष्ट वनों की स्थापना कर रहा है। प्रदेश में बीते दिनों कई विशिष्ट वन स्थापित किए जा चुके हैं। अब 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) पर सभी 75 जनपदों में वंदे मातरम् वाटिका स्थापित की जाएगी। यह वाटिका पर्यावरण संरक्षण के साथ ही राष्ट्रभक्ति का भी संदेश देगी। राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूर्ण होने पर 'एक पेड़ मां के नाम' के तहत हर जनपद में 150 पौधों का रोपण किया जाएगा। जनसहभागिता से इस वाटिका को बसाया जाएगा। अवध वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी सितांशु पांडेय ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर कुकरैल पिकनिक स्पॉट में वंदे मातरम् वाटिका को विस्तार दिया जाएगा। यहां अशोक चक्र बनवाया गया है, इसकी 24 तीलियों के बाहर के क्षेत्र में अशोक के पौधे लगाए जाएंगे। पौधों की सुरक्षा के लिए इसके चारों तरफ फेंसिंग भी होगी। इसमें भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त/वर्तमान के अधिकारियों समेत समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से पौधरोपण कराया जाएगा।

राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूर्ण होने पर 'एक पेड़ मां के नाम' के तहत हर जनपद में किया जाएगा 150 पौधों का रोपण



हर जनपद में एक चयनित स्थल पर किया जाएगा 150 पौधों का रोपण

'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत 15 अगस्त को सभी जिलों में 'वंदे मातरम् वाटिका' स्थापित की जाएंगी। इसके लिए वन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रत्येक जनपद में एक चयनित स्थान पर 150 पौधों का रोपण किया जाएगा, जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रकृति को समर्पित श्रद्धांजलि होगी। वन विभाग प्रत्येक जनपद में 'वंदे मातरम् वाटिका' विकसित करेगा। इसमें स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप छायादार, फलदार और पर्यावरण संरक्षण में उपयोगी प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। इन पौधों के देखभाल की जिम्मेदारी स्थानीय स्तर पर तय की जाएगी, जिससे अभियान स्थायी हरित धरोहर का रूप ले सके।

सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा से लोक भवन तक पदयात्रा

विस्थापित परिवार साझा करेंगे विभाजन की पीड़ा

- विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर सीएम योगी के नेतृत्व में निकलेगी मौन पदयात्रा

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर विभाजन की त्रासदी को याद करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मौन पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। शुक्रवार (14 अगस्त) को लखनऊ में जीपीओ स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा से लोक भवन तक प्रस्तावित पदयात्रा उन लोगों को श्रद्धांजलि देने का माध्यम बनेगी, जिन्होंने विभाजन के दौरान अपार पीड़ा झेली। जारी कार्यक्रम के अनुसार, लोकभवन प्रेक्षाग्रह में विभाजन विभीषिका से प्रभावित विस्थापित परिवारों के सदस्यों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर दिया जाएगा। साथ ही विभाजन की त्रासदी पर आधारित प्रदर्शनी, लाइव पेंटिंग और लघु फिल्म के माध्यम से उस दौर की पीड़ा और संघर्ष को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाएगा। इस दौरान सीएम योगी भी संबोधित करेंगे। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, राज्यसभा सदस्य डॉ. दिनेश शर्मा, राज्यसभा सदस्य ब्रजलाल, महापौर लखनऊ सुषमा खर्कवाल, विधान परिषद सदस्य डॉ. महेंद्र कुमा सिंह, विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा, विधान परिषद सदस्य रामचंद्र प्रधान, विधान परिषद सदस्य इंजी. अवनीश कुमार सिंह, विधान परिषद सदस्य डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल, विधान विधायक बख्शी का तालाब योगेश शुक्ला, विधायक लखनऊ पूर्व ओपी श्रीवास्तव, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा ब्रज बहादुर, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा अर्चना मिश्रा, महानगर अध्यक्ष भाजपा आनंद द्विवेदी, प्रतिनिधि, पंजाबी समाज, प्रतिनिधि, सिख समाज, प्रतिनिधि सिंधी समाज और प्रतिनिधि, बंगाली समाज समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे।

फास्ट न्यूज

आशियाना में नाले में गिरी कार

मोहनलालगंज । लखनऊ के आशियाना में गुरुवार दोपहर 1 बजे एक कार अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। हादसे के वक्त कार में 71 साल का चालक, उनका 8 साल का नाती और एक आया सवार थीं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नगर निगम व अग्निशमन विभाग की मदद से तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

पिता की मौत के बाद शव से लगवाया अंगूठा

लखनऊ । लखनऊ के रहीमाबाद के खड़ौहा गांव में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि पिता की मौत के बाद उनके इकलौते बेटे ने जमीन पर कब्जे के लिए शव के अंगूठे का निशान सादे कागज पर लगवा लिया। इस काम में उसने अपने चचेरे भाई की मदद ली। मौके पर मौजूद गांव वालों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया जो अब सामने आया है। परिजनों के मुताबिक, खड़ौहा निवासी छत्रपाल (75) और उनकी पत्नी शिवदेवी के साथ उनके बेटे महेंद्र और बहू लक्ष्मी का लंबे समय से विवाद चल रहा था। आरोप है कि दोनों बुजुर्गों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था।

निधि पांडेय बनी लखनऊ की एसडीएम

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल किया गया है। शासन ने 7 अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें अपर जिलाधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट और उपजिलाधिकारी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। बलरामपुर की अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ज्योति राय को अपर आयुक्त, आजमगढ़ मंडल बनाया गया है। वहीं बांदा के नगर मजिस्ट्रेट संदीप केला को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), बलरामपुर की जिम्मेदारी दी गई है।

108 आकांक्षात्मक विकासखंडों की रैंकिंग में सैदनगर ने मारी बाजी

- जुलाई की रैंकिंग में 70.03 अंक के साथ प्रदेश में हासिल किया प्रथम स्थान
- प्रयागराज का बहरिया विकासखंड 69.7 अंक प्राप्त कर दूसरे और संभल का असमौली 68.82 अंक प्राप्त कर तीसरे स्थान पर
- पांच थीम के 50 इंडीकेटर्स के आधार पर विकासखंडों का किया जाता है प्रति माह मूल्यांकन

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। योगी सरकार द्वारा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और पिछड़े क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना का प्रयास रंग ला रहा है। इसी के तहत प्रदेश के 108 आकांक्षात्मक विकासखंडों में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं संबद्ध सेवाएं, सामाजिक विकास तथा आधारभूत अवसंरचना जैसे पांच प्रमुख क्षेत्रों में निर्धारित 50 इंडीकेटर्स पर काम किया जा रहा है। इन इंडीकेटर्स की प्रगति की नियमित समीक्षा और रैंकिंग के माध्यम से विकासखंडों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है, जिसमें रामपुर जनपद के सैदनगर विकासखंड ने आकांक्षात्मक विकासखंडों की जुलाई-26 की रैंकिंग में प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। रामपुर जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के 108 आकांक्षात्मक विकासखंडों में चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में स्वास्थ्य एवं पोषण को 30 प्रतिशत, शिक्षा को 30 प्रतिशत, कृषि एवं संबद्ध सेवाओं को 20 प्रतिशत, आधारभूत अवसंरचना को 15 प्रतिशत तथा सामाजिक विकास को 5 प्रतिशत का भारांक दिया गया है।

योगी सरकार ने गोमती को निर्मल बनाने की कवायद की तेज, सीवेज प्रबंधन का बड़ा एक्शन प्लान तैयार

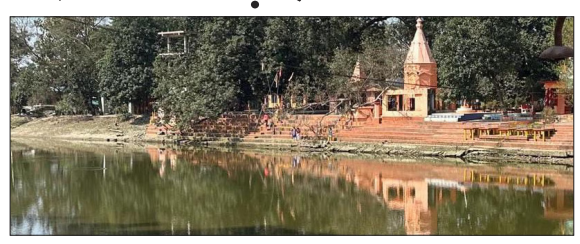
गोमती में गिर रहे 45 नालों को लेकर अब होगी कार्रवाई

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। योगी सरकार प्रदेश में नदियों को प्रदूषण को दर करने के लिए जोर-शोर से काम कर ही है। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ में गोमती नदी को सीवेज प्रदूषण से मुक्त करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई है। शहर से निकलने वाले सीवेज को सीधे गोमती में पहुंचने से रोकने के लिए नालों की टैपिंग, फ्लो डायवर्जन, एसटीपी की क्षमता बढ़ाने और नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। ड्रोन सर्वे के बाद गोमती में गिरने वाले 45 नालों की पहचान हुई है। अब इन नालों के जरिए नदी में पहुंच रहे सीवेज का शोधन सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग एसटीपी से जोड़ने की योजना पर काम हो रहा है। शहर में उत्पन्न सीवेज के शोधन के लिए कुल 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित हैं। इनकी कुल शोधन क्षमता करीब 629.5 एमएलडी है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक वास्तविक डिस्चार्ज और मौजूदा शोधन क्षमता के बीच अंतर बना हुआ है। ऐसे में गोमती में सीधे पहुंचने वाले सीवेज को रोकने के साथ ही शोधन क्षमता को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करना जरूरी है। लखनऊ में गोमती नदी करीब 30 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है। नगर निगम के रिकॉर्ड में गोमती में गिरने वाले 33 नालों का उल्लेख था।



गोमती में सीवेज रोकने की तैयारी, 160, 150 और 65 एमएलडी फ्लो डायवर्जन की योजना



- नमामि गंगे योजना से बदलेगी गोमती की तस्वीर, नालों की टैपिंग से एसटीपी तक पहुंचाया जाएगा सीवेज
- गोमती में प्रदूषण रोकने को तैयार हुआ मास्टर प्लान, पीएफआर एनएमसीजी को भेजी गई
- पीपराघाट-धैला में मॉड्यूलर एसटीपी, मरवारा और दौलतगंज प्लांट भी होंगे अपग्रेड

45.56 लाख आबादी, 7.52 लाख घर

वर्ष 2026 में लखनऊ नगर की अनुमानित आबादी करीब 45.56 लाख है। शहर में कुल 110 वार्ड हैं और करीब 7.52 लाख घर हैं। इनमें से लगभग 4.01 लाख यानी 53.32 प्रतिशत घर सीवरेज नेटवर्क से जुड़े हैं। ऐसे में सीवरेज नेटवर्क का विस्तार और नालों के जरिए गोमती में पहुंच रहे प्रदूषित पानी को रोकना नदी संरक्षण के लिए बड़ी चुनौती है। आंकड़ों के अनुसार लखनऊ में आबादी के सापेक्ष करीब 546.77 एमएलडी घरेलू सीवेज (गंदा और अपशिष्ट जल) उत्पन्न होता है, जबकि वास्तविक डिस्चार्ज करीब 880.70 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रति दिन) है। इसमें 690.33 एमएलडी सीवेज नालों के माध्यम से और 190.71 एमएलडी सीवर नेटवर्क के जरिए प्रवाहित होता है।

धारा-34 के विशेष अभियान में 2.21 लाख से अधिक वाद निस्तारित

योगी सरकार में राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण को मिली रफ्तार

- लाखों मामलों का हुआ निपटारा
- धारा-80 (भू-उपयोग परिवर्तन) के 49,855 वादों का निस्तारण किया गया
- धारा- 116 कुर्रा-बंट-वारा के वादों का 22,451 निस्तारण किया गया

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार की त्वरित न्याय और जनस-मस्याओं के प्रभावी निस्तारण की नीति के तहत राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों के निस्तारण की प्रक्रिया को लगातार तेज किया जा रहा है। शासन स्तर से की जा रही नियमित मॉनिटरिंग और विशेष अभियानों का असर राजस्व वादों के निस्तारण के आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। सीमांकन/पैमाइश से संबंधित धारा-24 के तहत 31 दिसंबर 2025 तक 28,556 वाद विचाराधीन थे। 1 जनवरी से 31 जुलाई 2026 तक 91,472 नए वाद आए, जिनमें से 39,645 वादों का निस्तारण किया गया। वर्तमान में 80,383 वाद विचाराधीन हैं। पांच वर्ष से अधिक पुराने लंबित वादों की संख्या महज 24 है। धारा-24 के तहत सबसे अधिक विचाराधीन वादों वाले जिलों में प्रयागराज, प्रतापगढ़, लखनऊ, अमेठी और मथुरा शामिल हैं। नामांतरण/दाखिल-खारिज से संबंधित धारा-34 में भी बड़े स्तर पर निस्तारण किया गया। 31 दिसंबर 2025 तक 48,910 वाद विचाराधीन थे। 1 जनवरी से 31 जुलाई 2026 के बीच 14,70,133 वाद आयोजित हुए, जिनमें से 10,96,814 वादों का निस्तारण किया गया। वहीं, 45 दिन से अधिक अवधि से लंबित नामांतरण वादों के निस्तारण के लिए 15 से 25 जून 2026 तक चलाए गए विशेष अभियान में ही 2,21,667 वादों का निस्तारण किया गया। धारा-80 के तहत भू-उपयोग परिवर्तन से जुड़े मामलों में 1 जनवरी से 31 जुलाई 2026 तक 28,797 वाद आए, जबकि 49,855 वादों का निस्तारण किया गया।



धारा-24, 34 और 80 के वादों के निस्तारण में तेजी

पुराने मामलों के निस्तारण पर विशेष जोर

योगी सरकार द्वारा राजस्व न्यायालयों में पुराने और लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि विशेष अभियान, नियमित समीक्षा और तकनीक आधारित मॉनिटरिंग के माध्यम से लंबित वादों के निस्तारण की गति बढ़ी है। योगी सरकार का लक्ष्य है कि लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण, आमजन को समयबद्ध न्याय और राजस्व संबंधी मामलों में पारदर्शी एवं सुगम व्यवस्था उपलब्ध कराना है।

अब स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ेंगे सर्वोदय विद्यालयों के विद्यार्थी

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित 5 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम शुरू

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। प्रदेश के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देने और उन्हें डिजिटल युग की आवश्यकताओं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने की दिशा में समाज कल्याण विभाग ने 5 जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम की शुरुआत की है। FIRST ORIGIN NextGen Edutech Pvt. Ltd. के सहयोग से CSR के माध्यम से शुरू इस पहल के प्रथम चरण में 5 विद्यालयों में एक-एक स्मार्ट क्लासरूम तैयार किया गया है।

इसी क्रम में बुधवार को गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में उद्घाटन एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री असीम अरुण ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव समाज कल्याण अनुराग यादव, निदेशक समाज कल्याण संजीव सिंह, उपनिदेशक श्री जे राम और FIRST ORIGIN के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुज कुमार वर्मा उपस्थित रहे।

निदेशक श्री संजीव सिंह ने बताया कि प्रदेश में 103 सर्वोदय विद्यालय संचालित हैं। पायलट प्रॉजेक्ट के तहत निडोरी (गाजियाबाद), बदनौरा (बुलंदशहर), हस्तिनापुर (मेरठ), बरेली और पीलीभीत में स्मार्ट क्लासरूम शुरू हुए हैं। इनमें स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट पैनल, दो एयर कंडीशनर व वुडेन फ्लोरिंग की सुविधा है।

राज्यमंत्री श्री असीम अरुण ने कहा कि स्मार्ट क्लासरूम केवल पढ़ाई का तरीका बदलने की पहल नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य को नई दिशा देने का प्रयास है।



चुनौती : ईडी-सीबीआई से जांच करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी

आय से अधिक संपत्ति का आरोप एससी पहुंचे राहुल

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ । कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इसमें उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के आरोपों का CBI और ED से वेरिफिकेशन कराने के निर्देश दिए थे। मामले में 17 अगस्त को सुनवाई होगी। दरअसल, कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया था। उन्होंने CBI और ED से इसकी जांच कराने की मांग की थी। इसके बाद कोर्ट ने आरोपों के वेरिफिकेशन के आदेश दिए थे। इस मामले में CBI विग्नेश शिशिर से पूछताछ भी कर चुकी है।



भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर ने 25 अप्रैल को लखनऊ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें राहुल गांधी की संपत्ति की जांच CBI और ED से कराने की मांग की थी। उन्होंने याचिका में CBI निदेशक, ED निदेशक, CBDT चेयरमैन, SFIO निदेशक, गृह मंत्रालय, राजस्व विभाग, कार्मिक विभाग (DoPT) और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय समेत 10 केंद्रीय एजेंसियों को पक्षकार बनाया है।

राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में एक ट्रांसफर याचिका भी दाखिल की है। इसमें उन्होंने इस मामले को लखनऊ बेंच से दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की मांग की है। राहुल ने यह याचिका 7 अगस्त को दाखिल की थी।



तस्वीर याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर की है। इस मामले में CBI ने एस. विग्नेश शिशिर से बुधवार (12 अगस्त) को 7 घंटे और मंगलवार को 6 घंटे पूछताछ की थी।

सीबीआई बीजेपी कार्यकर्ता विग्नेश से 13 घंटे पूछताछ कर चुकी है

एस. विग्नेश शिशिर मंगलवार को CBI के जांच अधिकारी के सामने पेश हुए थे। उनसे करीब 6 घंटे तक पूछताछ हुई। इसके बाद दूसरे दिन भी उन्हें बुलाया गया, जहां करीब 7 घंटे तक सवाल-जवाब का सिलसिला चला। विग्नेश शिशिर के मुताबिक, पूछताछ के दौरान उन्होंने भारत और विदेश से जुड़े कथित लेन-देन, विदेश यात्राओं और अन्य आरोपों से संबंधित जानकारी और दस्तावेज जांच अधिकारी को उपलब्ध कराए।

कूड़े और बजबजाती नालियां देख प्रभारी मंत्री भड़के

लखनऊ । लखनऊ में गुरुवार को लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने औचक निरीक्षण किया। अयोध्या दास प्रथम, अयोध्या दास द्वितीय, फैजुल्लागंज द्वितीय और गोमतीनगर वार्ड में जगह-जगह कूड़े के ढेर और बजबजाती नालियां देखकर मंत्री भड़क गए। इसके बाद नगर आयुक्त द्वारा कार्यदाई संस्था लायन एनवायरो पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जोन 4 के जेडएसओ पंकज शुक्ला और एसएफआई रश्मि का पांच दिनों की सैलरी कटौती करने का निर्देश दिया गया है। इनकी शिकायत पहले भी पार्षदों ने की थी। जोन तीन के एक सुपरवाइजर राजेश खन्ना को निलंबित किया गया है। निरीक्षण में सबसे खराब स्थिति फैजुल्लागंज द्वितीय वार्ड में मिली। महीनों से नालियां साफ नहीं हुई थीं। करोड़ों रुपये खर्च के बाद भी जमीनी स्तर पर काम न दिखने पर मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा जनता के पैसे से भुगतान लेने के बाद भी एजेंसियां काम नहीं करेंगी तो कठोर कार्रवाई होगी।

यूपीएसडीएम और आईआईए के बीच हुआ एमओयू

युवाओं को मिलेगा इंडस्ट्री का सीधा एक्सपोजर

- युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुरूप रोजगार और अप्रेंटिसशिप से सीधे जोड़ा जाएगा।
- प्रशिक्षण को उद्योगों की वास्तविक जरूरतों से जोड़ने पर जोर।

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के युवाओं को उद्योगों की आधुनिक आवश्य-कताओं के अनुरूप कुशल बनाने तथा उन्हें रोजगार और अप्रेंटिसशिप के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (IIA) के बीच गुरुवार को समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के मिशन निदेशक पुलकित खरे, संयुक्त निदेशक मयंक गंगवार मौजूद रहे।

इस समझौते का प्रमुख उद्देश्य इंडस्ट्री-इंस्टीट्यूट लिंकेज को मजबूत करना, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट के अवसर बढ़ाना, इंडस्ट्री एक्सपोजर उपलब्ध कराना तथा प्रशिक्षार्थियों की रोजगार क्षमता को बेहतर बनाना है। इसके माध्यम से प्रशिक्षण व्यवस्था को उद्योगों की वास्तविक जरूरतों से जोड़ते हुए युवाओं को व्यावहारिक एवं रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

मिशन निदेशक पुलकित खरे ने कहा कि प्रशिक्षण को अधिक व्यावहारिक और उद्योगपरक बनाने के लिए उद्योगों द्वारा आवश्यक रॉ मैटेरियल UPSDM प्रशिक्षण केंद्रों को उपलब्ध कराया जाएगा।

निकली तिरंगा रैली, 4-5 हजार लोग शामिल

हर घर तिरंगा अभियान के तहत शहर में दिखा उत्साह

अभियान

तमसा संकेत, एजेंसी

उन्नाव। स्वतंत्रता दिवस से पहले उन्नाव में 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत गुरुवार को भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। गांधी चौराहे से शुरू हुई रैली शास्त्री पार्क तक पहुंची। रैली में जिलाधिकारी घनश्याम मीणा, पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह, सदर विधायक पंकज गुप्ता समेत जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और बड़ी संख्या में शहरवासियों ने हिस्सा लिया। तिरंगा हाथों में लेकर निकले लोगों ने देशभक्ति का संदेश दिया। रैली में जिलाधिकारी घनश्याम मीणा और पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह की मौजूदगी रही। सदर विधायक पंकज गुप्ता समेत अन्य जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कार्यक्रम में सहभागिता की।



रैली में शामिल हुए हजारों लोग

तिरंगा रैली में करीब चार से पांच हजार लोगों की भागीदारी रही। इसमें स्कूली बच्चों के साथ युवा, जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी-कर्मचारी और विभिन्न वर्गों के नागरिक शामिल हुए। बड़ी संख्या में लोगों के एक साथ तिरंगा लेकर सड़क पर उतरने से शहर का माहौल देशभक्ति से सराबोर नजर आया।

जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने कहा कि तिरंगा महोत्सव और आगामी स्वतंत्रता दिवस को लेकर जिले के लोगों में काफी उत्साह है। उन्होंने जनपदवासियों से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की प्रेरणा से चल रहे तिरंगा महोत्सव में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक अपने घर पर तिरंगा फहराकर देश के प्रति सम्मान और समर्पण की भावना प्रदर्शित करे।

रैली ने दिखाया लोगों का उत्साह

गांधी चौराहे से शास्त्री पार्क तक निकली तिरंगा रैली में उमड़ी हजारों लोगों की भीड़ ने उन्नाव में 'हर घर तिरंगा' अभियान को लेकर उत्साह का प्रदर्शन किया। स्कूली बच्चों से लेकर आम नागरिकों तक की भागीदारी ने कार्यक्रम को व्यापक जनसहभागिता प्रदान की। रैली के माध्यम से जिले में स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश भी दिया गया।

जिले में बांटे जा चुके करीब साढ़े चार लाख तिरंगे

जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में करीब साढ़े चार लाख तिरंगे एकत्रित कर वितरित किए जा चुके हैं। विभिन्न क्षेत्रों में लोग अपने-अपने तरीके से तिरंगा महोत्सव में भागीदारी कर रहे हैं। बच्चों और आम नागरिकों की ओर से भी अभियान को लेकर अलग-अलग तरह के नवाचार किए जा रहे हैं।

जगह-जगह हुआ रैली का स्वागत

गांधी चौराहे से शास्त्री पार्क तक निकली रैली के दौरान शहर के विभिन्न स्थानों पर लोगों ने तिरंगा लहराकर प्रतिभागियों का स्वागत किया। कई स्थानों पर लोगों ने भारत माता की जय और देशभक्ति के नारों के साथ उत्साह बढ़ाया। रैली के दौरान स्वतंत्रता दिवस को लेकर लोगों में उत्साह और राष्ट्रप्रेम की भावना साफ दिखाई दी।

राष्ट्रप्रेम और तिरंगे के सम्मान का संदेश

अधिकारियों के मुताबिक 'हर घर तिरंगा' अभियान का उद्देश्य लोगों में राष्ट्रप्रेम की भावना को मजबूत करने के साथ राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान बढ़ाना है। तिरंगा रैली के जरिए नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अभियान में सहभागी बनने के लिए प्रेरित किया गया।

विरासत और विकास यात्रा प्रगति पर

राज्य सूचना आयुक्त ने विकास कार्यों की समीक्षा की

तमसा संकेत, एजेंसी



बाराबंकी। बाराबंकी में विरासत के संरक्षण के साथ विकास की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। यह बात राज्य सूचना आयुक्त डॉ. दिलीप अग्निहोत्री ने रामनगर स्थित निरीक्षण गृह में कही। उन्होंने जन सूचना अधिकारियों को अपने दायित्वों का पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन करने के निर्देश दिए। डॉ. अग्निहोत्री ने कहा कि जिले में विरासत को सम्मान देने के साथ विकास कार्यों को भी गति दी जा रही है। तीर्थ स्थलों का विकास केवल बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सनातन संस्कृति, राष्ट्रीय चेतना और भारतीय परंपराओं के संरक्षण से भी जुड़ा है। प्रदेश सरकार इसी सोच के साथ धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। यात्रा के दौरान उन्होंने रामनगर स्थित बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन-पूजन किया। उन्होंने भगवान लोधेश्वर महादेव मंदिर के प्रस्तावित भव्य कॉरिडोर का भी उल्लेख किया। कहा कि श्री काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर लोधेश्वर महादेव मंदिर का विकास होने से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और बाराबंकी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि बाराबंकी को करीब साढ़े पांच सौ करोड़ रुपये की विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात मिली है।

फास्ट न्यूज

गंगा का पानी घरों में घुसा

उन्नाव। उन्नाव में गंगा नदी का जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण गुरुवार सुबह आठ बजे गंगा का जलस्तर 112.16 मीटर दर्ज किया गया। यह चेतावनी बिंदु से ऊपर बह रही है। बढ़ते जलस्तर के कारण तटवर्ती इलाकों में नए क्षेत्रों में पानी फैलने लगा है। इससे पहले से बाढ़ से प्रभावित लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

उन्नाव। उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के पटेल नगर में बुधवार रात एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला का शव उसके घर में मिला। गुरुवार सुबह मायके पक्ष के परिजनों ने मौत को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई। मृतका की पहचान किरण जायसवाल (55) के रूप में हुई है, जो स्व. अनिल जायसवाल की पत्नी थीं। उनके पति की कोरोना काल में मौत हो चुकी थी। किरण पटेल नगर स्थित अपने घर में अकेली रहती थीं। उनका मायका सीतापुर जिले में है। बुधवार रात करीब दस बजे उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।

ओम फार्मा पर एंटी नारकोटिक्स टीम की छापेमारी पूरी

उन्नाव। उन्नाव के नेहरूबाग इंडस्ट्रियल एरिया स्थित ओम फार्मा पर बुधवार दोपहर एंटी नारकोटिक्स विभाग की टीम ने छापेमारी की। यह कार्रवाई कंपनी में नशीले पदार्थों से संबंधित सामग्री के उत्पादन की शिकायत मिलने के बाद की गई। लखनऊ एएटीएफ यूनिट की 8 सदस्यीय टीम ने लगभग 8 घंटे तक जांच की। कच्चे माल और तैयार सामग्री से संबंधित अभिलेखों की पड़ताल की। जांच के दौरान कंपनी में विजयावटी (भांग) बनाए जाने की जानकारी भी सामने आई।

ग्राम समाज की जमीन कब्जा मुक्त

इगलास में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के आदेश पर मोजीपुर में हुई कार्रवाई

तमसा संकेत, एजेंसी

इगलास। इगलास तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत मोजीपुर में नवीन परती और ग्राम समाज की जमीन को दबंगों के कब्जे से मुक्त कराया गया है। यह कार्रवाई नवागत ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आयुष जायसवाल के आदेश पर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची टीम ने की। बताया गया कि मोजीपुर में कुछ दबंगों ने नवीन परती और ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। हाल ही में वृक्षारोपण अभियान के तहत इस जमीन पर लगाए गए पौधे भी दबंगों द्वारा उखाड़ दिए गए थे। ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती रामवती देवी के पति गुलवीर सिंह ने तहसील मुख्यालय पहुंचकर पौधे उखाड़े जाने की शिकायत की थी। इसके बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आयुष जायसवाल ने राजस्व निरीक्षक श्रीकांत और लेखपाल नरेंद्र मित्तल की टीम को पुलिस बल के साथ मौके पर भेजा। टीम ने जमीन को चिन्हित कर कब्जा मुक्त कराया। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन से ग्राम प्रधान रामवती देवी ने जेसीबी मशीन मंगवाकर कूड़ा-कचरा हटवाया। इसके बाद जमीन पर तार फिक्सिंग का कार्य भी शुरू करा दिया गया है।



बेटे ने मांगी उच्चस्तरीय जांच, नई सोशल मीडिया आईडी से अभद्र टिप्पणियों का लगाया आरोप

भाजपा विधायक के परिवार पर साइबर उत्पीड़न का आरोप

तमसा संकेत, एजेंसी

हरदोई। हरदोई के गोपामऊ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक श्यामप्रकाश के परिवार से जुड़ा कथित साइबर उत्पीड़न का मामला सामने आया है। विधायक के बेटे और टड़ियावां ब्लॉक प्रमुख रवि प्रकाश ने सोशल मीडिया के जरिए मामले को उठाते हुए प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार से उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी अपील की है। रवि प्रकाश ने 12/13 अगस्त की देर रात करीब दो बजे फेसबुक पर एक पोस्ट साझा की। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों से उनके और उनके पिता विधायक श्यामप्रकाश के सोशल मीडिया प्रोफाइल को कुछ नई आईडी द्वारा लगातार फॉलो किया जा रहा है। उनका कहना है कि इन्हीं खातों से उनकी सोशल मीडिया पोस्ट पर आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणियां की जा रही हैं। रवि प्रकाश के मुताबिक प्रारंभिक स्तर पर ऐसे कई सोशल मीडिया अकाउंट सामने आए हैं, जो हाल ही में बनाए गए प्रतीत होते हैं। इन खातों पर सामान्य गतिविधियां भी बेहद कम होने का दावा किया गया है। इसी आधार पर उन्होंने आशंका जताई कि कुछ लोग सुनियोजित तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं।



ब्लॉक प्रमुख रवि प्रकाश ने आरोप लगाया कि संबंधित सोशल मीडिया खातों से जातिसूचक गालियां, व्यक्तिगत अपमान और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने इसे सामान्य सोशल मीडिया गतिविधि न मानते हुए मामले की गंभीरता से जांच किए जाने की मांग की है।

मुख्यमंत्री समेत कई अधिकारियों से शिकायत

रवि प्रकाश ने मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्रियों, कैबिनेट मंत्री असीम अरुण, एडीजी जोन लखनऊ, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक हरदोई समेत कई अधिकारियों से शिकायत की है। उन्होंने संबंधित सोशल मीडिया खातों की गंभीरता से जांच कराने की मांग की है।

राजनीतिक छवि खराब करने की साजिश का आरोप

ब्लॉक प्रमुख ने आशंका जताई कि सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी और उनके पिता की राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने तथा परिवार के बीच भय का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

हालांकि, इन आरोपों के पीछे वास्तविकता क्या है और सोशल मीडिया खातों का संचालन कौन कर रहा है, यह तकनीकी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

परिवार को नुकसान होने पर जिम्मेदारी तय करने की बात

फेसबुक पोस्ट में रवि प्रकाश ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि यदि उन्हें या उनके परिवार के किसी सदस्य को कोई नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

डीएम ने कस्तूरबा विद्यालयों का निरीक्षण किया

मेधावी छात्राओं को सम्मानित कर आईएएस बनने के टिप्स दिए

तमसा संकेत, एजेंसी

बाराबंकी। बाराबंकी जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने गुरुवार दोपहर 1:00 बजे मुजीबपुर और देवा स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हाईस्कूल की 15 मेधावी छात्राओं और राज्य स्तरीय कुरास प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया। डीएम ने छात्राओं से संवाद करते हुए उन्हें जीवन में लक्ष्य हासिल करने के लिए जिज्ञासु बनने की प्रेरणा दी। उन्होंने विशेष रूप से आईएएस बनने के इच्छुक छात्राओं को नियमित अध्ययन करने, प्रश्न पूछने और नई चीजें सीखने की आदत विकसित करने की सलाह दी। उन्होंने छात्राओं को सोशल मीडिया पर अनावश्यक समय बिताने से बचने और इसके बजाय पुस्तकों तथा समाचार पत्रों को पढ़ने की आदत डालने का सुझाव दिया। जिलाधिकारी ने बताया कि इससे सामान्य ज्ञान बढ़ेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी सहायता मिलेगी। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने छात्राओं के साथ भोजन भी किया और विद्यालय की समग्र व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने विद्यालय परिसर में साफ-सफाई बेहतर रखने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, इंटरलॉकिंग कार्य कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। डीएम ने जोर देकर कहा कि बालिकाओं की शिक्षा और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।





घर में झगड़े के बाद तकिए से मुंह दबाया, एक दिन पहले की थी मारपीट

घरेलू विवाद के बाद पत्नी की हत्या

तमसा संकेत, एजेंसी

हरदोई। हरदोई के संडीला कोतवाली क्षेत्र में घरेलू विवाद के चलते एक पति ने अपनी पत्नी की कथित तौर पर हत्या कर दी। बुधवार देर रात करीब 11:30 बजे मुरारनगर गांव में शराब के नशे में धुत पति आशाराम ने 50 वर्षीय पत्नी रामा का तकिए से मुंह और नाक दबा दिया। दम घुटने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के पुत्र की तहरीर पर आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में लिया गया है। बताया गया कि संडीला से करीब नौ किलोमीटर दूर मुरारनगर गांव निवासी आशाराम ई-रिक्शा चलाता है। मृतका की सास मुन्नी देवी के मुताबिक, आशाराम शराब पीने का आदी है और इसी वजह से पति-पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता रहता था। आरोप है कि आशाराम अक्सर रामा के साथ मारपीट भी करता था। परिजनों के मुताबिक, घटना से एक दिन पहले मंगलवार दोपहर को भी आशाराम ने रामा के साथ मारपीट की थी। विवाद बढ़ने पर आसपास के ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर दोनों को शांत कराया था। इसके बाद मामला शांत हो गया था, लेकिन बुधवार रात फिर से दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। बुधवार देर रात करीब 11:30 बजे आशाराम कथित तौर पर शराब के नशे में घर पहुंचा। इसके बाद किसी बात को लेकर पत्नी रामा से उसका विवाद होने लगा। परिवार के लोगों के मुताबिक, देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और आशाराम ने बिस्तर पर रखे तकिए से रामा का मुंह और नाक दबा दिया।



पुत्र की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज

प्रभारी निरीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि मृतका के पुत्र की तहरीर के आधार पर आरोपी पति आशाराम के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

वारदात : पिता बोले- बीमारी से गई जान, हत्या की सूचना से पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम

8वीं के छात्र की संदिग्ध हालात में मौत

तमसा संकेत, एजेंसी

हरदोई। हरदोई के मझिला थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह कक्षा आठ के 12 वर्षीय छात्र पंकज कुमार का शव कमरे में मिलने से हड़कंप मच गया। इसी दौरान किसी व्यक्ति ने यूपी-112 पर फोन कर छात्र की हत्या किए जाने की सूचना दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। छात्र के पिता ने उसकी मौत बीमारी के कारण होने की बात कही है। पुलिस ने मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट करने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है मझिला थाना क्षेत्र के भिठारा मजरा आलमनगर निवासी लड़ैते का 12 वर्षीय बेटा पंकज कुमार उच्च प्राथमिक विद्यालय आलमनगर में कक्षा आठ में पढ़ता था। परिजनों के मुताबिक, पंकज पिछले करीब एक महीने से बुखार से पीड़ित था। उसका इलाज भी चल रहा था और परिवार उसकी तबीयत में सुधार की उम्मीद कर रहा था। परिजनों ने बताया कि बुधवार रात पंकज की तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई थी। पिता लड़ैते के मुताबिक, गुरुवार सुबह उसे डॉक्टर के पास ले जाने की तैयारी की जा रही थी। इसी बीच सुबह कमरे में पंकज मृत अवस्था में मिला। छात्र की मौत के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई। पंकज की मौत के बाद परिजनों ने रिश्तेदारों को सूचना दी और अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी।



पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने की कही बात

पुलिस के पहुंचने पर अधिकारियों ने छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की बात कही। इस पर पिता लड़ैते ने पुलिस को बताया कि बेटे की मौत बीमारी के कारण हुई है। हालांकि, पुलिस ने मामले को संदिग्ध परिस्थितियों से जुड़ा मानते हुए मौत का सही कारण पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम को जरूरी बताया। पंकज के शव का पोस्टमार्टम कराने की बात सुनकर उसकी मां अमरा भावुक हो गईं। उन्होंने पुलिस से पोस्टमार्टम न कराने की गुहार लगाई। परिवार बीमारी के कारण मौत होने की बात कह रहा है, जबकि अज्ञात व्यक्ति की ओर से हत्या की सूचना दिए जाने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है।

पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

थानाध्यक्ष वीर बहादुर सिंह ने बताया कि गांव के एक व्यक्ति की ओर से छात्र की मौत की सूचना पुलिस को दी गई थी। परिस्थितियों को देखते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही छात्र की मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह सामने आने के बाद उसी के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने छात्र की मौत को लेकर लगाए गए हत्या के आरोप की भी जांच शुरू कर दी है।

थानाध्यक्ष वीर बहादुर सिंह ने बताया कि गांव के एक व्यक्ति ने छात्र की मौत की सूचना दी थी। संदिग्ध परिस्थितियों को देखते हुए शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण स्पष्ट होगा। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बचाव को व्यापारियों को किया जागरूक

बाराबंकी। बाराबंकी में बढ़ते साइबर अपराध और निवेश के नाम पर होने वाली ठगी से लोगों को बचाने के लिए बुधवार दोपहर 2 बजे गल्ला मंडी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। साइबर क्राइम सेल बाराबंकी और उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की ओर से संयुक्त रूप से 'निवेश सुरक्षा जागरूकता अभियान' चलाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य व्यापारियों और आम लोगों को निवेश के नाम पर होने वाली साइबर ठगी से बचाव के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संगम कुमार रहे। इस दौरान साइबर अपराध से बचाव के विभिन्न उपायों की जानकारी दी गई। अधिकारियों और विशेषज्ञों ने बताया कि साइबर ठग अधिक मुनाफे का लालच देकर फर्जी निवेश योजनाओं, शेयर बाजार, ऑनलाइन ट्रेडिंग और अन्य माध्यमों से लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं।

छत से नीचे उतर रहे बुजुर्ग का पैर फिसला

अस्पताल ले जाते समय मौत, हरदोई में तेज हवा के कारण हादसा

तमसा संकेत, एजेंसी

हरदोई। हरदोई में बुधवार देर रात मौसम बदलने के दौरान छत से गिरकर एक बुजुर्ग की मौत हो गई। कछौना थाना क्षेत्र के बाण गांव में करीब 65 वर्षीय दिनेश चंद्र बाजपेई रात में घर की छत पर सो रहे थे। करीब 2 बजे अचानक तेज हवा चलने और बारिश का मौसम बनने पर वह छत से नीचे उतरने लगे। इसी दौरान पैर फिसलने से वह नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक, दिनेश चंद्र बाजपेई बुधवार रात घर की छत पर सो रहे थे। रात करीब 2 बजे अचानक मौसम बदल गया और तेज हवा चलने लगी। बारिश होने के आसार देखकर वह छत से नीचे आने लगे। इसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और पैर फिसल गया। वह छत से नीचे गिर पड़े। गिरने की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे। हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आई थीं। हादसे के बाद दिनेश चंद्र के भतीजे शुभम बाजपेई और शिवम बाजपेई उन्हें आनन-फानन में निजी साधन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कछौना लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक उपचार किया।



सम्पादकीय

जेपीसी में एफसीआरए



विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी एफसीआरए में संशोधन वाले विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति में भेजने से पक्ष-विपक्ष के बीच सहमति बनने के आसार कम ही हैं, क्योंकि विपक्षी दल इसे वापस लेने की मांग पर अड़े थे। इस कानून में संशोधन पर विपक्ष के साथ अमेरिकी सांसद को भी आपत्ति थी। इसके अतिरिक्त ईसाई संगठन भी इस कानून में संशोधन-परिवर्तन के खिलाफ थे।

उचित यही होता कि सरकार इस विधेयक पर संसद में चर्चा कराने को प्राथमिकता देती और फिर आवश्यक समझती तो उसे जेपीसी को भेजती। बिना किसी चर्चा के इस विधेयक को जेपीसी भेजने से ऐसा लग रहा है कि सरकार किसी दबाव में आ गई। जो भी हो, किसी कानून में संशोधन सरकार का अधिकार है। विपक्ष प्रस्तावित संशोधनों पर अपनी आपत्ति जता सकता है, लेकिन वह इस पर अड़ नहीं सकता कि संशोधन किया ही न जाए। आखिर इसके पहले भी एफसीआरए में संशोधन किया गया है और यह इसलिए किया गया था कि कुछ गैर-सरकारी संगठन विदेशी धन के बल पर पर्यावरण संरक्षण की आड़ में विकास विरोधी हरकतें करते हुए पाए गए थे। एफसीआरए यह तय करता है कि एनजीओ, ट्रस्ट आदि विदेश से प्राप्त दान किन उद्देश्यों पर खर्च कर रहा है। एफसीआरए यह भी सुनिश्चित करता है कि विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल देश की संप्रभुता, सुरक्षा और आंतरिक शांति के विरुद्ध न होने पाए। हालांकि एफसीआरए में यह प्रविधान है कि राजनीतिक दल, नेता, उम्मीदवार, जज, सरकारी कर्मचारी आदि विदेशी चंदा प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कई संस्थाएं यह स्पष्ट करने से इन्कार करती हैं कि उन्होंने विदेश से मिले पैसे किस मद में खर्च किए? ऐसे भी मामले सामने आ चुके हैं कि दान जिस उद्देश्य से लिया गया, उसे खर्च किसी अन्य मकसद के लिए किया गया। इससे भी चिंताजनक यह है कि विदेशी धन पाने वाली कई संस्थाएं राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध काम करती हुई पाई गई हैं। क्या यह किसी से छिपा है कि कुडनकुलम परमाणु परियोजना के खिलाफ धरना-प्रदर्शन करने वाले संगठन ऐसा ही करते पाए गए थे? यह निष्कर्ष उस संप्रग सरकार का था, जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही थी। क्या यह विडंबना नहीं कि आज यही कांग्रेस एफसीआरए में संशोधन के खिलाफ है? देश में कार्यरत एनजीओ एक तरह का उद्यम बन गए हैं।

कई एनजीओ संदिग्ध चरित्र वाले हैं और उन पर देश हित विरोधी कार्यों और खासकर विकास विरोधी माहौल बनाने तथा मतांतरण में लिप्त होने के आरोप लगते रहे हैं। इसे देखते हुए एफसीआरए में उपयुक्त संशोधन किए ही जाने चाहिए। इसलिए और भी, क्योंकि संप्रभु देश को यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि विदेशी धन का दुरुपयोग न होने पाए।

> विधेयक में एक महत्वपूर्ण संतुलनकारी प्रावधान यह भी है कि धार्मिक स्थल की धार्मिक प्रकृति को बनाए रखना अनिवार्य होगा। नामित प्राधिकरण किसी ऐसे स्थल को दूसरे उद्देश्य में बदल या उसकी धार्मिक प्रकृति समाप्त नहीं कर सकेगा।

विदेशी चंदे पर नियंत्रण और संतुलन की अपेक्षा



12 अगस्त 2026 का दिन भारतीय संसद के लिए इसलिए महत्वपूर्ण रहा कि विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 यानी एफसीआरए विधेयक को लोकसभा ने 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति-जेपीसी के पास भेज दिया। यह फैसला केवल एक विधेयक को संसदीय प्रक्रिया के अगले चरण में भेजना नहीं है, बल्कि उस व्यापक बहस का अवसर है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी धन की पारदर्शिता, धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं की स्वायत्तता, नागरिक समाज की भूमिका और लोकतांत्रिक अधिकार-सभी एक साथ जुड़े हुए हैं। विधेयक को जेपीसी के पास भेजे जाने से सरकार और विपक्ष के बीच तत्काल टकराव को कुछ हद तक विमर्श में बदलने का अवसर मिला है। एफसीआरए का इतिहास भी इस बहस की गंभीरता को समझने में मदद करता है। विदेशी धन के माध्यम से देश के राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर बाहरी प्रभाव की आशंकाओं को देखते हुए 1976 में पहली बार कानून बनाया गया था। वर्ष 2010 में इसे नए एफसीआरए कानून से प्रतिस्थापित किया गया और उसके बाद 2020 सहित विभिन्न चरणों में इसके प्रावधान अधिक कठोर होते गए। आज यह कानून केवल विदेशी चंदे की प्राप्ति और उसके उपयोग का लेखा-जोखा रखने का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े विमर्श का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।

आंकड़े इस विषय की व्यापकता बताते हैं। पीआरएस के अनुसार 15 जुलाई 2026 तक 14,449 एफसीआरए प्रमाणपत्र सक्रिय थे, जबकि 22,498 रद्द और 15,212 समाप्त माने गए। 2019 से 2022 के बीच 13,520 संगठनों को लगभग 55,741 करोड़ रुपये का विदेशी अंशदान मिला। इन आंकड़ों को देखकर यह सवाल स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी धनराशि का उपयोग कहां, किस उद्देश्य से और किस स्तर की निगरानी के साथ हुआ? लेकिन इसके साथ दूसरा प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है-क्या किसी संस्था का एफसीआरए पंजीकरण समाप्त हो जाना अपने आप में किसी वित्तीय या आपराधिक अनियमितता का प्रमाण माना जा सकता है? सरकार के अपने स्पष्टीकरण के अनुसार भी पंजीकरण समाप्त होने के कई कारण हो सकते हैं और हर समाप्ति को गलत काम से जोड़ना उचित नहीं है। यहीं से प्रस्तावित संशोधन का सबसे संवेदनशील पक्ष सामने आता है। विधेयक में 'नामित प्राधिकरण' की व्यवस्था प्रस्तावित है। यदि किसी संस्था का एफसीआरए पंजीकरण रद्द हो जाता है, वह स्वयं पंजीकरण छोड़ देती है या उसका प्रमाणपत्र नवीनीकरण न होने के कारण समाप्त हो जाता है, तो विदेशी अंशदान और उससे निर्मित संपत्तियां पहले अस्थायी रूप से इस प्राधिकरण के अधीन आ सकती हैं। यदि निर्धारित अवधि में पंजीकरण बहाल नहीं होता तो संपत्तियां स्थायी रूप से निहित की जा सकती हैं तथा उन्हें सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए उपयोग या बेचने का प्रावधान है। बिक्री से प्राप्त राशि और अप्रयुक्त विदेशी अंशदान भारत की समेकित निधि में जमा किए जाने का प्रस्ताव है। भारत में समय-समय पर ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें विदेशी वित्तपोषण के दुरुपयोग, वित्तीय अनियमितताओं अथवा राष्ट्रीय हित से टकराने वाली गतिविधियों को लेकर सवाल उठे हैं। इसलिए एफसीआरए का मूल उद्देश्य-विदेशी अंशदान को पारदर्शी, उत्तरदायी और वैध उद्देश्यों तक सीमित रखना-न तो अनुचित है और न ही लोकतंत्र विरोधी। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता और प्रशासनिक शक्ति के विस्तार के बीच एक स्पष्ट रेखा भी होनी चाहिए। यही इस विधेयक की असली परीक्षा है। यदि किसी संस्था ने विदेशी धन का इस्तेमाल आतंकवाद, हिंसा, अलगाववाद, जबरन या प्रलोभन आधारित धर्मांतरण, राजनीतिक अस्थिरता अथवा भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में किया है, तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रहित में ऐसी कठोरता आवश्यक है। मगर दूसरी ओर यदि कोई संस्था अस्पताल चला रही है, गरीबों के लिए शिक्षा उपलब्ध करा रही है, पर्यावरण संरक्षण कर रही है, महिलाओं और बच्चों के लिए काम कर रही है अथवा प्राकृतिक आपदा में राहत पहुंचा रही है, तो केवल तकनीकी या प्रक्रियागत चूक के कारण उसके वर्षों के सामाजिक कार्य और विदेशी अंशदान से निर्मित परिसंपत्तियों पर तत्काल सरकारी नियंत्रण स्थापित हो जाना चिंता का विषय बन सकता है। यही कारण है कि जेपीसी के पास जाना इस विधेयक के लिए एक सकारात्मक अवसर है। संसद में बहुमत से कानून पारित करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन जिन कानूनों का प्रभाव हजारों संस्थाओं, लाखों लाभार्थियों और देश के व्यापक नागरिक समाज पर पड़ता हो, उनकी बारीकी से जांच लोकतंत्र को मजबूत करती है। जेपीसी में विपक्ष अपनी आपत्तियां रख सकता है, सरकार अपने तर्क स्पष्ट कर सकती है और विधि विशेषज्ञों, सामाजिक संगठनों, धार्मिक संस्थाओं, वित्तीय विशेषज्ञों तथा सुरक्षा एजेंसियों के अनुभवों को भी सामने लाया जा सकता है।

इसके अलावा प्रभावित संस्था को 90 दिनों के भीतर पुनरीक्षण का अधिकार और जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील का प्रावधान दिया गया है। सरकार ने यह भी बताया है कि पंजीकरण बहाल होने पर अस्थायी रूप से निहित संपत्तियां और अप्रयुक्त धन वापस किए जाएंगे। ये प्रावधान स्वागत योग्य हैं, लेकिन सवाल यह रहेगा कि इन अधिकारों की वास्तविक स्वतंत्रता और प्रक्रिया कितनी प्रभावी होगी। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन नवीनीकरण से जुड़ा है। 2026 के नियमों में पिछले दो वित्तीय वर्षों में कम से कम 10 लाख रुपये विदेशी अंशदान के उपयोग को सक्रिय संस्था की पहचान के रूप में रखा गया है। साथ ही गतिविधि और राज्य-विशिष्ट पंजीकरण तथा अधिक विस्तृत उपयोग संबंधी जानकारी देने की व्यवस्था भी की गई है। यह व्यवस्था निष्क्रिय संस्थाओं पर नियंत्रण के लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन जेपीसी को यह भी देखना होगा कि क्या हर छोटी लेकिन वास्तविक सामाजिक संस्था के लिए 10 लाख रुपये खर्च करना व्यावहारिक मानदंड है। सामाजिक उपयोगिता का मूल्य केवल धनराशि से नहीं किया जा सकता।

एफसीआरए की बहस को केवल 'सरकार बनाम विपक्ष' या 'राष्ट्रवाद बनाम नागरिक स्वतंत्रता' के द्वंद्व में सीमित करना भी उचित नहीं होगा।

ललित गर्ग

स्वास्थ्य

उबड़-खाबड़ पर्वत श्रृंखला को पार कर,नदी स्वयं अपनी मंजिल का पथ तय करती है। स्वस्थ तन,मन और भावनात्मक सोच से ही जीवन की नैया भव चक्र के पार उतरती है।पर यह सब कुछ इतना आसान भी तो नहीं है की हंसते ,मुस्कराते हुए हम लक्ष्य को प्राप्त कर लें । इसीलिए हमे कदम-कदम पर पथ दृष्टा, कर्मो के निर्जण और संकल्प की जरूरत पड़ती है। हमारा तन ही तो जीवन का मूल स्थूल स्तम्भ है । हमको इसलिए इसकी सुस्वस्थता पर सात्विक दम्भ होना चाहिए । हमको स्वस्थ रहते स्वास्थ्य की कीमत समझ में नहीं आती हैं । इसकी असली कीमत हम गफलत में जब इसे खो देते है तब जानी जाती हैं । हवा, पानी, व्यायाम आदि- आदि के अतिरिक्त, स्वास्थ्य का मुख्य और सीधा पोषक खाद्य है। हम स्वास्थ्य स्वाद के पीछे अखाद्य खा-खा कर बिगाड़ लेते हैं । हमारे बेचारे पेट को तो कोई स्वाद नहीं चाहिए। यह तो हमारे बीच की दलाल जिह्वा ही है जो स्वाद के लालच में शरीर को नाना बीमारियों का प्रसाद देती रहती है। अतः अपेक्षित है कि हम स्वास्थ्य के मूल पोषक सात्विक एवं पौष्टिक आहार पर ध्यान दें । वह हम साथ ही समय-समय पर उदर एवं पाचन क्रिया के विश्राम पर देखें । अब मन में यह प्रश्न आ सकता हैं कि क्या वास्तव में स्वास्थ्य धन हैं? अंग्रेजी में कहावत है HEALTH IS WEALTH क्या सच में यह सही है ? देखने में तो यह आ रहा है कि धन के पीछे अन्धी दौड़ में हम लोग स्वास्थ्य-धन की एकदम अनदेखी करते जरा भी नहीं सकुचाते हैं। और मज़े की बात है इस लापरवाही का स्वास्थ्य पर साक्षात विपरीत प्रभाव का भान ही नहीं कर पाते हैं। मैं तब सोचता हूं क्या स्वास्थ्य ही धन है । यह बता कर चले जाने वाले इसके सही अर्थ से अनजान थे ? या समझदार से समझदार भी आज इसकी अनदेखी करने वाले स्वास्थ्य शब्द का ही अर्थ नहीं जानना चाहते? Health is wealth , पहला सुख निरोगी काया, धन से दवा खरीद सकते है स्वास्थ्य नहीं मिलता हैं । यह तो सच्चाई है।

> प्रदीप छाजेड़

भारत सरकार ने...

अशोक भाटिया

अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ का सच और सरकार की त्वरित कार्रवाई

आज की दुनिया में सीमा की रक्षा केवल बंदूकों और मिसाइलों से नहीं होती, बल्कि यह हाइब्रिड वॉरफेयर के युग में प्रवेश कर चुकी है। चीन इस रणनीति का पुराना खिलाड़ी है, जहां वह बिना एक भी गोली चलाए, भ्रामक सूचनाओं और मनोवैज्ञानिक दबाव के जरिए अपने विरोधी को रक्षात्मक मुद्रा में लाने की कोशिश करता है।

अरुणाचल प्रदेश भारत का वह सुदूर पूर्वी मुकुट है, जिसकी भौगोलिक स्थिति और सामरिक महत्व हमेशा से देश की सुरक्षा नीति के केंद्र में रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया और कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक हलकों से उठी चीनी सेना की 'धीमी घुसपैठ' की खबरों ने एक बार फिर राष्ट्रीय विमर्श को गरमा दिया है। एक ऐसे दौर में जब सीमा पर दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण शांति बनी हुई है, घुसपैठ की ऐसी खबरें न केवल रणनीतिक रूप से संवेदनशील हैं, बल्कि आंतरिक मोर्चे पर भी असमंजस पैदा करती हैं। हालांकि, इस बार सरकार और भारतीय सेना ने न केवल इन दावों को पूरी तरह से निराधार और अफवाह करार दिया, बल्कि असाधारण सक्रियता दिखाते हुए स्थिति को तुरंत स्पष्ट किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर के नेतृत्व में नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि केंद्र सरकार सीमा सुरक्षा और उससे जुड़ी सूचनाओं के प्रति कितनी सजग और एक्शन मोड में है। अख़बारों और मुख्यधारा के विमर्श के लिए यह केवल एक तात्कालिक घटना नहीं है, बल्कि यह इस बात का गंभीर विश्लेषण करने का अवसर है कि



आधुनिक दौर में सीमा सुरक्षा केवल अग्रिम चौकियों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह सूचना युद्ध और मनोवैज्ञानिक मोर्चे पर भी लड़ी जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई खबरों की जड़ें 'पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल' की एक तथाकथित फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट में खोजी जा सकती हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ऊपरी सुबनसिरी जिले के तक्सिंग सेक्टर में चीनी सैनिकों ने भारतीय चरवाहों और शिकारियों के पारंपरिक रास्तों पर कब्जा कर लिया है। इस दावे को हवा तब मिली जब सोशल मीडिया पर कुछ धुंधले और असत्यापित वीडियो प्रसारित होने लगे, जिनमें चीनी बुनियादी ढांचे और सैनिकों की उपस्थिति का दावा किया गया था। इस प्रकार की सूचनाएं जैसे ही सार्वजनिक पटल पर आईं, वैसे ही भारतीय सेना के शीर्ष कमान और देश के नीति-नियंताओं ने मोर्चा संभाल लिया। सेना ने स्पष्ट और कड़े शब्दों में कहा कि सीमा पर भारत ने अपनी एक इंच जमीन भी नहीं खोई है। ऊपरी सुबनसिरी के दुर्गम इलाकों में स्थित सभी अग्रिम चौकियां पूरी तरह से भारतीय बलों के नियंत्रण में हैं। सेना ने स्पष्ट किया कि जिसे 'घुसपैठ' के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, वह असल में चीन द्वारा अपनी सीमा के भीतर किया जा रहा बुनियादी ढांचा विकास हो सकता है, जिसे जानबूझकर भारतीय क्षेत्र के भीतर दिखाकर सनसनी फैलाने का प्रयास किया गया। सरकार का यह त्वरित और पारदर्शी रुख सराहनीय है, क्योंकि अक्सर सीमावर्ती मुद्दों पर आधिकारिक सूचनाओं में देरी अफवाहों को खाद-पानी देने का काम करती है। इस विवाद की पृष्ठभूमि को समझने के लिए भारत और चीन के बीच हालिया कूटनीतिक और भौगोलिक घटनाक्रमों पर नजर डालना जरूरी है। भारत सरकार ने पिछले दिनों एक बड़ा कदम उठाते हुए आधिकारिक मानचित्रों पर अरुणाचल प्रदेश की 27 प्रमुख जगहों के नाम पूरी तरह से भारतीय पहचान के अनुरूप दर्ज किए थे। यह कदम चीन के उस पुराने पैंतरे का सीधा जवाब था, जिसके तहत वह अरुणाचल के विभिन्न स्थानों का बार-बार 'पुनः नामकरण' कर उन्हें अपनी संप्रभुता का हिस्सा बताने की कोशिश करता रहा है। भारत के इस संप्रभु अधिकार और कड़े रुख से बीजिंग निश्चित रूप से असहज हुआ था। विदेश मंत्रालय ने इस मोर्चे पर हमेशा की तरह यह दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा; चीन की किसी भी कृत्रिम नामावली या काल्पनिक दावों से यह ऐतिहासिक और जमीनी हकीकत नहीं बदलने वाली है। इसलिए, जब भारत ने कूटनीतिक स्तर पर अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर ली हो, तब देश के भीतर से ही सीमा सुरक्षा पर इस तरह के असत्यापित और कमज़ोर दावे उठना पूरी रक्षा रणनीति को प्रभावित कर सकते हैं।

किसी भी राज्य...

मो0 इकबाल खाँ

शादी विवाह अनुदान योजना से पिछड़ा वर्ग के गरीब परिवारों को मिला आर्थिक सहारा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मंतव्य है कि समाज के हर व्यक्ति का शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास समान रूप से हो और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश सरकार ने अपने सभी विभागों में अनेक योजनाओं का संचालन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से चलायी जा रही सभी योजनाएं केवल वित्तीय सहायता देने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पिछड़े वर्ग के परिवारों को सम्मानजनक जीवन, बेहतर शिक्षा, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रहा है। प्रदेश का पिछडा वर्ग कल्याण विभाग इस संकल्प को धरातल पर उतारने में सबसे अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

किसी भी राज्य या राष्ट्र की वास्तविक प्रगति तब तक अधूरी मानी जाती है, जब तक कि समाज का अंतिम व्यक्ति और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग विकास की मुख्यधारा से न जुड़ जाए। उत्तर प्रदेश, जो अपनी विशाल आबादी और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है, वर्तमान में समावेशी विकास (प्दबसनेपअम ळतवूजी) के एक अभूतपूर्व दौर से गुजर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मूल मंत्र को आत्मसात् करते हुए समाज के पिछड़े वर्गों (ओ०बी०सी०) के उत्थान के लिए योजनाबद्ध और पारदर्शी ढंग से शादी/विवाह योजना लागू की है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में 210 करोड़ रूपये बजट का प्राविधान किया गया है, जिसके अन्तर्गत योजना का वार्षिक लक्ष्य 1,05,000 को लाभान्वित करना है, जिसके सापेक्ष अब तक 64,584 आवेदन प्राप्त हुऐ हैं, जिसमें 5,032 लाभार्थियों को 10.064 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है। वर्ष 2025-26 में 1,16,000 गरीब परिवार की पुत्रियों के विवाह हेतु सम्बन्धितों के खाते में 232 करोड़ रुपये हस्तान्तरित किये गये है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जहाँ सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की प्रमुख योजनाओं में विवाह अनुदान योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर अन्य पिछडा वर्ग (अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर) के गरीब परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाता है, जिससे परिवार पर आर्थिक बोझ कम हो सके। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी को प्रति विवाह रु0 20,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को दिया जाता है जिनकी वार्षिक आय रु0 1,00,000 से अधिक नहीं है। विवाह के समय कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है। आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को ऑनलाइन जाति प्रमाण-पत्र का विवरण देना होता है। योजना में निराश्रित एवं विधवा महिलाओं को प्राथमिकता देने का भी प्रावधान किया गया है। एक परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों को इस योजना का लाभ दिया जा सकता है।

जरा हटके

वर्तमान में भारत में ...

दुर्गेश्वर राय

भारत समेत दुनिया भर में अदृश्य संबल से आर्थिक क्रांति तक पहुँचा केयरगिविंग

सभ्यता के आरम्भ से ही मनुष्य एक-दूसरे पर आश्रित रहा है। जीवन के शुरुआती दौर में शिशु की सुरक्षा से लेकर वृद्धावस्था में जर्जर शरीर को संबल देने तक, देखभाल का मानवीय स्वभाव ही समाज की निरंतरता का सबसे बड़ा स्तंभ रहा है। परंतु सदियों तक स्नेह, त्याग और नैतिक उत्तरदायित्व के आवरण में लिपटा यह कार्य आधुनिक अर्थशास्त्र की मुख्यधारा से बाहर ही रहा। केयरगिविंग यानी देखभालकर्ताओं की यह संकल्पना मूल रूप से मानव विज्ञान, समाजशास्त्र और स्त्रीवादी अर्थशास्त्र के संगम से उपजी है। औद्योगिक क्रांति के बाद जब काम का विभाजन घर और बाहर की सीमाओं में हुआ तो उत्पादक कार्य केवल उसे माना गया जिसके बदले सीधे तौर पर धन का लेन-देन होता था। इसके विपरीत, घर की चारदीवारी के भीतर बच्चों, बुजुर्गों, बीमारों और दिव्यांगों की देखभाल को प्राकृतिक दायित्व मानकर आर्थिक गणनाओं से बाहर कर दिया गया। बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में जब श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी और परिवार का पारंपरिक ढांचा बदला, तब अर्थशास्त्रियों ने यह पहचानना शुरू किया कि यदि घर में देखभाल का अदृश्य आधार न हो तो मुख्य धारा का कोई भी उत्पादक कार्य संभव ही नहीं हो सकता। यहीं से केयर इकॉनमी और औपचारिक केयरगिवर्स की संकल्पना को एक पृथक और अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक-सामाजिक क्षेत्र के रूप में मान्यता मिली।

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में केयरगिविंग एक गंभीर जनसांख्यिकीय और आर्थिक चुनौती के रूप में उभर कर सामने आया है। दुनिया भर में अभूतपूर्व जनसांख्यिकीय बदलाव हो रहे हैं। एक तरफ जहाँ चिकित्सा विज्ञान की प्रगति से औसत जीवन प्रत्याशा बढ़ी है, वहीं दूसरी तरफ जन्म दर में गिरावट आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, विश्व की जनसंख्या तेजी से बुजुर्ग हो रही है। यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका जैसे विकसित देश इस समय केयर क्राइसिस यानी देखभाल के गंभीर संकट से जूझ रहे हैं, जहाँ देखभाल करने वालों की भारी कमी हो चुकी है। इस समय वैश्विक स्तर पर अधिकांश देखभाल का बोझ अब भी अवैतनिक केयरगिवर्स, विशेषकर महिलाओं और लड़कियों के कंधों पर है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, दुनिया भर में रोजाना लगभग 16 अरब घंटे का अवैतनिक देखभाल कार्य किया जाता है जो यदि किसी न्यूनतम मजदूरी पर आंका जाए तो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 10 प्रतिशत से अधिक के बराबर होगा। इस भारी-भरकम बोझ के कारण करोड़ों महिलाएं औपचारिक रोजगार, उच्च शिक्षा और राजनीतिक भागीदारी से वंचित रह जाती हैं। वहीं दूसरी ओर, वैतनिक केयरगिवर्स जैसे नर्स, आया, ओल्ड-एज होम वर्कर और होम-केयर अटेंडेंट की स्थिति भी बहुत संतोषजनक नहीं है। इस क्षेत्र को अक्सर कम वेतन, सामाजिक सुरक्षा के अभाव, अनौपचारिक कार्य परिस्थितियों और सम्मान की कमी से जोड़कर देखा जाता है। इसी वैश्विक और राष्ट्रीय परिदृश्य की पृष्ठभूमि में भारत के नीति आयोग द्वारा जारी विस्तृत रिपोर्ट रीइमेजिनिंग केयर : स्ट्रैटेजीज फॉर एम्पावरिंग केयरगिवर्स इन विकसित भारत 2047, एक युगांतरकारी रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट समस्याओं को सूचीबद्ध करने के साथ ही वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में केयरगिविंग को एक प्रमुख आर्थिक और सामाजिक इंजन के रूप में पुनर्परिभाषित करती है। भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में जहाँ पारिवारिक संरचनाएं तेजी से संयुक्त से एकल परिवार में बदल रही हैं और महिलाओं की श्रमबल में भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, वहाँ यह रिपोर्ट अत्यंत प्रासंगिक हो जाती है। नीति आयोग की यह रिपोर्ट मुख्य रूप से दोहरे दृष्टिकोण पर आधारित है। पहला, देश के भीतर एक मजबूत, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, और दूसरा, भारत को दुनिया भर के लिए एक प्रशिक्षित और कुशल केयरगिवर्स का वैश्विक आपूर्ति केंद्र बनाना। नीति आयोग की इस रिपोर्ट का पहला महत्वपूर्ण पक्ष भारत के भीतर मौजूदा देखभाल प्रणाली का औपचारिक और मानकीकृत ढांचा तैयार करना है। वर्तमान में भारत में केयरगिविंग का अधिकांश क्षेत्र असंगठित और अनियमित है। नीति आयोग ने इसके समाधान के लिए एक राष्ट्रीय देखभाल नीति और एक एकीकृत राष्ट्रीय देखभालकर्ता परिषद के गठन का स्पष्ट प्रस्ताव रखा है। यह परिषद देश में केयरगिवर्स के लिए न्यूनतम मानक तय करेगी, उनकी शिक्षा व प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम निर्धारित करेगी और उनका एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करेगी। इसके साथ ही, रिपोर्ट में देखभाल करने वालों के व्यावसायिक और मानसिक कल्याण पर विशेष जोर दिया गया है। चौबीसों घंटे अपनों या मरीजों की सेवा में लगे केयरगिवर्स अक्सर गंभीर शारीरिक और मानसिक तनाव (बर्नआउट) से गुजरते हैं। रिपोर्ट में उनके लिए रेस्पाइट केयर यानी विश्राम देखभाल, परामर्श सेवाएं और सामाजिक सुरक्षा लाभ जैसे स्वास्थ्य बीमा और पेंशन का प्रावधान करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट का दूसरा और बेहद दूरदर्शी पक्ष भारत की जनसांख्यिकीय लाभांश की क्षमता का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग करना है। जहाँ पश्चिमी देश और पूर्वी एशिया की विकसित अर्थव्यवस्थाएँ बुजुर्ग होती आबादी और श्रमबल की कमी का सामना कर रही हैं, वहीं भारत के पास युवाओं की सबसे बड़ी आबादी है। नीति आयोग ने पहचाना है कि विश्व भर में आने वाले दशकों में करोड़ों प्रशिक्षित केयरगिवर्स की आवश्यकता होगी। यदि भारत अपने युवाओं, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भाषा, तकनीकी कौशल, प्राथमिक चिकित्सा, जेरिएट्रिक यानी वृद्धजनों की देखभाल और बाल देखभाल का उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करे, तो भारत पूरी दुनिया के लिए केयरगिवर्स का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। इससे न केवल घरेलू स्तर पर लाखों नए और सम्मानजनक रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बल्कि विदेशी मुद्रा प्रेषण के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। नीति आयोग की रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रस्तावित प्रसिद्ध 5आर फ्रेमवर्क को भारत के अनुकूल ढालने पर बल देती है। इसमें पहला कदम देखभाल के काम के आर्थिक और सामाजिक मूल्य को पहचानना है।

महिला ठग ने 1.40 करोड़ हड़पे, 7 दिन पहले करवाई थी एफआईआर, रोते हुए मां-पिता पहुंचे

डॉक्टर ने 8वीं मंजिल से कूदकर जान दी

घटना

तमसा संकेत, एजेंसी

गोरखपुर। गोरखपुर में 45 साल के डॉक्टर ने अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। गुरुवार सुबह साढ़े 9 बजे खाना खाने के बाद डॉक्टर छत पर गए। करीब 15 मिनट तक टहले, फिर छत से छलांग लगा दी। चीख-पुकार सुनकर डॉक्टर की पत्नी दौड़कर नीचे पहुंचीं। डॉक्टर खून से लथपथ पड़े थे। आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस को डॉक्टर की जेब से एक पेज का सुसाइड नोट मिला। इसमें उन्होंने अपनी मौत के लिए महिला ठग गरिमा सिंह को जिम्मेदार बताया। पुलिस के



मुताबिक, डॉक्टर से गरिमा सिंह ने 1.40 करोड़ रुपए की ठगी की थी। इसके बाद से वह सदमे में थे। उन्होंने 7 दिन पहले गरिमा सिंह और उसके रेलवे अफसर पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, उससे एक दिन पहले ही पुलिस ने गरिमा और उसके पिता ध्रुव नारायण सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। घटना शहर के गोरखनाथ क्षेत्र की है। पशु चिकित्सक परमात्मा

डॉक्टर ने एफआईआर में कहा था- पैसे मांगे तो महिला ठग ने धमकाया

5 अगस्त को पशु चिकित्सक परमात्मा सिंह ने एम्स थाने में 1.40 करोड़ रुपए की ठगी का केस दर्ज कराया था। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया था कि महराजगंज के बरगदवां में डॉ. दिलीप कुमार सिंह पशु चिकित्साधिकारी के पद पर हैं। वह मेरे मित्र हैं। उन्हें पता था कि मैंने होम लोन लिया है। डॉ. दिलीप कुमार की गरिमा सिंह रिश्तेदार है। फरवरी- 2026 को गरिमा ने मुझे फोन किया। उसने मुझसे पूछा कि मेरा कोई लोन चल रहा है क्या? मैंने उसे बताया कि मेरा एक होम लोन चल रहा है। गरिमा ने कहा कि मैं अपने मित्र के साथ एक फाइनेंस फर्म में काम करती हूं। एक स्कीम है, जिसमें होम लोन क्लोज करा दिया जाता है।

सिंह (45) महराजगंज के नौतनवा में तैनात थे। उनकी पत्नी डॉ. सुमित्रा सिंह भी पशु चिकित्सक हैं। घटना की सूचना मिलते ही डॉक्टर के पिता पारस नाथ सिंह और मां कुंती सिंह मऊ से गोरखपुर पहुंचे। बेटे का शव देखकर दोनों फूट-फूटकर रोने लगे।

पत्नी बोलीं- बैंक से लगातार फोन आ रहे थे, पति डिप्रेशन में थे

पशु चिकित्सक परमात्मा सिंह राजेंद्र नगर कॉलोनी स्थित बसंत इनक्लेव की दूसरी मंजिल पर रहते थे। परिवार में उनकी पत्नी डॉ. सुमित्रा सिंह, बेटा अरिहंत सिंह (12) और बेटी बिन्नी (7) हैं। डॉ. सुमित्रा ने बताया- मेरे पति ने बैंक से लोन लेकर महिला ठग गरिमा सिंह को पैसे दिए थे। बैंक से लगातार फोन आ रहे थे।

इसके चलते वह डिप्रेशन में थे। वह कहते थे कि सवा लाख की सैलरी में 3 लाख रुपए की EMI होगी, तो क्या होगा? कैसे होगा? इतना बड़ा अमाउंट है, कैसे भरेंगे?



11वीं का छात्र पबजी में तीन लाख हारा

गर्लफ्रेंड से चेहरे पर खून, मुंह पर टेप वाली तस्वीर बनवाई

तमसा संकेत, एजेंसी

गोरखपुर। गोरखपुर में 11वीं के छात्र ने PUB-G में 3 लाख रुपए हारने के बाद अपने अपहरण की झूठी कहानी रच दी। गर्लफ्रेंड की मदद से AI से ऐसी फोटो बनवाई, जिसमें उसके मुंह पर टेप और शरीर पर खून के निशान दिख रहे थे। फोटो देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे बुरी तरह पीटा गया है। छात्र ने पिता को वॉट्सएप पर फोटो भेजी और मैसेज लिखा- 1 लाख रुपए भेज दो, नहीं तो बेटे की लाश मिलेगी। फोटो देखते ही पिता घबरा गए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने छात्र का फोन सर्विलांस पर लगाया। करीब 2 घंटे बाद मंगलवार रात 2 बजे उसे दोस्त के घर से पकड़ लिया। मामला जिला मुख्यालय से करीब 40 किमी दूर सिकरीगंज का है। 16 साल के छात्र



के पिता कपड़ा कारोबारी हैं। उसकी गर्लफ्रेंड दिल्ली में रहती है। सत्यप्रकाश संतकबीरनगर के धनघटा क्षेत्र में परिवार के साथ रहते हैं। उनका बेटा शहर के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में 11वीं में पढ़ता है। पुलिस के मुताबिक, छात्र को PUB-G खेलने की लत है। गेम खेलने के चक्कर में उसने दोस्तों और कुछ जानने वालों से पैसे उधार ले लिए। धीरे-धीरे उस पर करीब 3 लाख रुपए का कर्ज हो गया। लोगों ने पैसे मांगने शुरू किए तो उसने अपहरण की योजना बनाई।

फास्ट न्यूज

यूपी में गुटखा खाने पर आरपीएफ सिपाही सस्पेंड

गोंडा। गोंडा में गुटखा खाने के आरोप में RPF के कॉन्स्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। आरोप है कि कॉन्स्टेबल बुधवार शाम RPF के सुरक्षा सम्मेलन में गुटखा खा रहा था, तभी लखनऊ डिवीजन के सीनियर डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर अरुण त्रिपाठी की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने स्पीच रोककर कॉन्स्टेबल को फटकार लगाई और कार्रवाई के निर्देश दिए। गुरुवार सुबह कॉन्स्टेबल के सस्पेंशन का आदेश जारी कर दिया गया।

बीएसपी ने कानपुर के अंटू मिश्रा को पार्टी से निकाला

कानपुर। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने कानपुर के रहने वाले पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनंत मिश्रा उर्फ अंटू को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी से निष्कासित कर दिया। बसपा सुप्रीमो ने अपने एक्स अकाउंट से यह जानकारी दी है। अंटू मिश्रा का पार्टी से निकाले जाने के बाद हलचल तेज हो गई और इसे बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। अंटू मिश्रा ने भाजपा ज्वाइन करने की कोशिश की थी, लेकिन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) घोटाले के आरोपी होने के चलते उन्हें भाजपा ने पार्टी में शामिल नहीं किया था।

1500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की तिरंगा रैली

संभल। संभल में गुरुवार शाम 4 बजे भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने भव्य तिरंगा रैली निकाली। चंदौसी रोड स्थित कुरुक्षेत्र तीर्थ मंदिर से शुरू हुई करीब 4 किलोमीटर लंबी यात्रा में 1500 से अधिक कार्यकर्ता शामिल हुए।
माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने शुरुआत में करीब आधा किलोमीटर बाइक से यात्रा की।
कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर उन्होंने बाइक छोड़कर पदयात्रा शुरू कर दी।

बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ पड़ा महंगा, 28 स्कूली वाहनों के चालान

तमसा संकेत, संवादाता



मथुरा। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। प्रदेशव्यापी 15 दिवसीय विशेष प्रवर्तन अभियान मिशन सेफ फ्यूचर 2.0 के तहत मथुरा में चलाए गए सघन चेकिंग अभियान के दौरान 28 स्कूली वाहनों के चालान किए गए, जबकि पांच वाहनों को विभिन्न थानों में सीज कर दिया गया। उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त के निर्देश पर 11 अगस्त से 25 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। हाल के दिनों में स्कूली वाहनों से हुई दुर्घटनाओं को देखते हुए शासन ने बच्चों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान शुरू किया है। वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) राजेश राजपूत के निर्देशन में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सतेन्द्र कुमार सिंह, यात्रीकर अधिकारी संदीप चौधरी और पूजा सिंह ने जिले में संचालित स्कूल बसों, वैनों और अनुबंधित वाहनों की गहन जांच की। अभियान के दौरान वाहनों की फिटनेस, परमिट, प्राथमिक उपचार बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, चालकों की योग्यता और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई। जांच के दौरान कई वाहनों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी, फिटनेस प्रमाणपत्र की कमी और दस्तावेजों में अनियमितताएं पाई गईं। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई के दौरान बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया। किसी भी वाहन को तब तक सीज नहीं किया गया, जब तक उसमें सवार बच्चों को सुरक्षित रूप से उनके विद्यालय या गंतव्य तक नहीं पहुंचा दिया गया। वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी राजेश राजपूत ने विद्यालय प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि सभी स्कूल अपने वाहनों की फिटनेस और परमिट का नवीनीकरण तत्काल करा लें। विभाग की ओर से स्कूलों में सीधे नोटिस पहुंचाने के लिए कर्मचारियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि जिन वाहनों की फिटनेस समाप्त हुए 30 दिन से अधिक समय बीत चुका है और इसके बावजूद उनका नवीनीकरण नहीं कराया गया है, उनके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा 53 के तहत पंजीकरण निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी।

स्वच्छ ब्रज अभियान को मिली नई उड़ान

मथुरा-वृंदावन में नई पहल 'हम सबने यह ठाना है, ब्रज को स्वच्छ बनाना है' के संकल्प के साथ अभियान

तमसा संकेत, संवादाता

मथुरा। 'हम सबने यह ठाना है, ब्रज को स्वच्छ बनाना है' के संदेश के साथ नगर निगम मथुरा-वृंदावन ने ई-रिक्शा चालकों को स्वच्छता अभियान से जोड़ने की पहल की है। गुरुवार को वृंदावन की नवीन मंडी स्थित दारुक पार्किंग के पास जन-जागरूकता एवं स्वच्छता संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें ई-रिक्शा चालकों को स्वच्छ ब्रज का ब्रांड एंबेसडर बनाने की शुरुआत की गई। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं है, बल्कि नागरिक कर्तव्यों के प्रति संकल्प लेने का भी दिन है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने शहर और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभानी चाहिए। डीएम ने ब्रज क्षेत्र को स्वच्छ रखने के लिए पॉलीथिन के इस्तेमाल से बचने की अपील भी की।

ई-रिक्शाओं में लगाए गए डस्टबिन और स्वच्छता संदेश

ब्रज वैभव अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में ई-रिक्शा चालकों को स्वच्छता का संदेश लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। इसके लिए चयनित ई-रिक्शाओं में पोर्टेबल डस्टबिन और स्वच्छता संदेश वाली पट्टिकाएं लगाई गईं। चालकों से अपील की गई कि वे यात्रियों को सड़क पर कचरा फेंकने से रोकें और कचरे को निर्धारित स्थान पर डालने के लिए प्रेरित करें।



रोज हजारों लोगों से संपर्क में रहते हैं चालक

नगर आयुक्त ओजस्वी राज ने कहा कि ई-रिक्शा चालक प्रतिदिन बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के संपर्क में रहते हैं। ऐसे में वे स्वच्छता और नागरिक जिम्मेदारियों का संदेश व्यापक स्तर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने ई-रिक्शा चालकों से निर्धारित रूट पर चलने और यातायात नियमों का पालन करने की भी अपील की।

तिरंगा रैली को दिखाई हरी झंडी

कार्यक्रम के दौरान नगर निगम और ब्रज तीर्थ विकास परिषद की ओर से तैयार स्वच्छता एवं जन-जागरूकता वीडियो भी दिखाया गया। अतिथियों ने चयनित ई-रिक्शाओं पर राष्ट्रध्वज, स्वच्छता संदेश वाली पट्टिकाएं और डस्टबिन लगाए।
इसके बाद 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत ई-रिक्शाओं की तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान 'भारत माता की जय' और 'ब्रज को स्वच्छ बनाना है' के नारों से परिसर गूंज उठा।

2 दिन तलवार में धार लगाई, फिर ठेकेदार को काटा

गोरखपुर में आरोपियों के घर ताला पड़ा, पुलिस कर रही जर्मन शेफर्ड और गाय की देखभाल

तमसा संकेत, एजेंसी



गोरखपुर। गोरखपुर में बिजली विभाग के ठेकेदार शिव कुमार त्रिपाठी की 8 अगस्त को तलवार और बांके से वार कर हत्या कर दी गई। आरोपियों का घर अहिरौला में ठेकेदार के घर से 500 मीटर दूर है। 8 आरोपी गिरफ्तार हैं, सभी आरोपियों के घर पर ताला बंद है। सुरक्षा के लिहाज से उनके घर पर पुलिस फोर्स तैनात है। आरोपियों के घर पर जर्मन शेफर्ड कुत्ता और एक गाय घटना के बाद से ही भूखी-प्यासी बंधी है। पांच दिन से कुत्ता और गाय को पुलिसवाले खाना खिला रहे हैं। यह एक दिन की लड़ाई का नतीजा नहीं, बल्कि साल 2024 में हुई आदेश चौधरी हत्याकांड का बदला था। जिसे ठेकेदार के चचेरे भाइयों ने मिलकर अंजाम दिया था। इसी रंजिश में आदेश चौधरी परिवार के नाबालिग 12वीं के छात्र ने तलवार से वार कर ठेकेदार को मार डाला। आरोपी ने पुलिस से बताया कि आसानी से काट सके, इसलिए तलवार खरीदने के बाद उसमें दो दिन तक धार लगाई थी। बुधवार को अहिरौली गांव पहुंची। यहां गलियों में सन्नाटा पसरा था। दोपहर के समय गांव की महिलाएं घरों में दुबक कर बातें कर रही थीं। किसी से भी कुछ पूछने पर लोग बताने से इनकार कर दे रहे थे। यहां तक कि वहां कोई घटना हुई थी, इस बारे में भी वह अनजान बन रहे थे। शिव कुमार के घर पर इकलौता बेटा एडवोकेट आदित्य तिवारी सफेद कपड़ों में बैठकर घटना को यादकर बार-बार बिलख पड़ रहा है।

आईपीईसी में 'मानसिक शक्ति' कार्यक्रम

युवाओं को तनाव से निपटने और भेदभाव से बचने का संदेश

तमसा संकेत, संवादाता

साहिबाबाद। औद्योगिक क्षेत्र साइट-4 स्थित इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज (आईपीईसी) में गुरुवार को 'मानसिक शक्ति' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 'अवेयरनेस टू एक्शनः एम्पावरिंग यंग माइंड्स फॉर इनक्लूसिवनेस' थीम पर हुए कार्यक्रम में युवाओं को मानसिक रूप से मजबूत बनने के साथ-साथ लैंगिक समानता, सम्मान और संवेदनशील व्यवहार के लिए जागरूक किया गया। कार्यक्रम का आयोजन इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च (ICSSR), राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) और डॉ. अर्चिका फाउंडेशन के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम को 'उच्च शिक्षा में युवाओं की लैंगिक सोच और व्यवहार का अध्ययनः एआई पर आधारित दीर्घकालिक शोध' से भी जोड़ा गया है। इसका मकसद युवाओं



की सोच और व्यवहार को समझना और उन्हें जागरूकता से आगे बढ़कर सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉ. अर्चिका दीदी, चेयरपर्सन, डॉ. अर्चिका फाउंडेशन रहीं। उत्तराखंड हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस राजेश टंडन और स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन की डीसीपी नेहा यादव भी मौजूद रहीं। राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जस्टिस राजेश टंडन ने कहा कि महिलाओं को आजीविका, सम्मान और सुरक्षित कार्यस्थल का अधिकार मिलना जरूरी है। उन्होंने महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल बनाने पर जोर दिया।

रोज की छोटी आदतों से मजबूत होगी मानसिक शक्ति

डीसीपी नेहा यादव ने विद्यार्थियों को तनाव से निपटने के आसान तरीके बताए। उन्होंने गहरी सांस लेने, पर्याप्त नींद, ध्यान, व्यायाम, पढ़ने और अपने विचार लिखने जैसी आदतों को जीवन का हिस्सा बनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि रोजाना की छोटी-छोटी सकारात्मक आदतें मानसिक मजबूती बढ़ाने में मदद करती हैं। डॉ. अर्चिका दीदी ने कहा कि युवाओं को पढ़ाई, करियर और निजी जीवन में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मानसिक रूप से मजबूत रहना जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों को ध्यान की प्रक्रिया समझाई और उसका अभ्यास भी कराया।



'जागरूकता तभी कामयाब, जब व्यवहार में दिखे बदलाव'

आईपीईसी की उपाध्यक्ष ने कहा कि किसी विषय की जानकारी होना ही पर्याप्त नहीं है। जागरूकता तब सार्थक होती है, जब वह समझ, सहानुभूति और सकारात्मक कार्रवाई में बदलती है। उन्होंने कहा कि युवा केवल भविष्य नहीं, बल्कि आज के बदलाव के वाहक हैं। उनमें आत्मविश्वास, भावनात्मक संतुलन और दूसरों के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना जरूरी है। कार्यक्रम की संयोजक डॉ. पूजा त्रिपाठी ने कहा कि युवाओं को केवल तकनीकी शिक्षा देना पर्याप्त नहीं है। उन्हें सही-गलत की पहचान करने, रूढ़ियों पर सवाल उठाने, सम्मानजनक तरीके से संवाद करने और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने के लिए भी तैयार करना होगा।

वारदात : मां बोली- बॉयफ्रेंड के साथ गई थी, 3 महीने की प्रेग्नेंट थी

युवती की लाश मिली, हत्या का आरोप

तमसा संकेत, एजेंसी



कानपुर। कानपुर में गुरुवार सुबह 24 साल की गर्भवती युवती का शव आम के बगीचे में मिला। शव के मुंह से झाग निकल रहा था और शरीर नीला पड़ा था। मां ने प्रेमी पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। युवती की मां ने बताया कि बेटी करीब चार महीने पहले प्रेमी के साथ घर से चली गई थी। करीब एक महीने पहले वह घर लौटी तो बताया कि वह 3 महीने की गर्भवती है। इसके पांच दिन बाद वह एक दूसरे युवक के साथ फिर घर से चली गई। इसके 25 दिन बाद गांव के बाहर आम के बाग में उसकी लाश मिली। मामला घाटमपुर थानाक्षेत्र के एक गांव का है। पुलिस ने बताया कि परिजन संदिग्ध युवकों के बारे में अभी स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाए हैं। तहरीर मिलने के बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी। मौत की वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ होगी। घाटमपुर थानाक्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती के पिता राजमिस्त्री का काम करते हैं। मां ने बताया कि युवती का शहर में रहने वाले एक युवक से प्रेम संबंध था। बेटी उससे आए दिन मिलने जाती थी। घरवाले उसे प्रेमी से मिलने से मना करते थे लेकिन वह नहीं मानती थी। पिता की डांट के बाद वह नाराज रहने लगी थी। मां के मुताबिक, करीब 4 महीने पहले बेटी बिना बताए प्रेमी के साथ घर से चली गई थी। करीब एक महीने पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद

> **थाना प्रभारी ने बताया- परिजन फिलहाल संदिग्ध युवकों की स्पष्ट पहचान और उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं दे पाए हैं। पुलिस मोबाइल की कॉल डिटेल और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से जांच कर रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से मौत की वजह स्पष्ट होगी।**

हुआ, जिसके बाद वह घर लौट आई। उसने परिजनों को बताया कि वह करीब 3 महीने की गर्भवती है। परिजनों ने उसे समझाया, लेकिन 5 दिन बाद वह एक दूसरे युवक के साथ फिर घर से चली गई। इसके बाद गुरुवार सुबह उसका शव गांव से करीब 500 मीटर दूर आम के बाग में मिला। घटनास्थल पर पहुंची डॉग स्क्वायड की टीम का रूलर नाम का जर्मन शेफर्ड घटनास्थल से पश्चिम दिशा में करीब एक किलोमीटर दूर केवड़िया रोड तक गया। इसके बाद वह वापस लौट आया। इससे पुलिस को अंदेशा है कि युवती को कार से लेकर आए लोगों में से कोई व्यक्ति केवड़िया रोड की तरफ गया होगा। वहीं, परिजनों ने युवती के प्रेमी पर हत्या कर शव को बगीचे में फेंकने का आरोप लगाया है।



मोबाइल फोन कब्जे में, कॉल डिटेल खंगाल रही पुलिस

घाटमपुर थाना प्रभारी मनोज सिंह भदौरिया पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच कर कई साक्ष्य जुटाए। टीम को मौके से शराब की बोतल और गिलास भी मिले हैं। इसके अलावा जमीन पर कार के टायर के निशान भी मिले हैं।

गोरखपुर-जौनपुर समेत 8 शहरों में बारिश, सड़कें बनीं तालाब

बाइकें फंसकर बंद हुईं, काशी में घाट डूबे, शव जलाने के लिए घंटों इंतजार

तमसा संकेत, एजेंसी

वाराणसी/कानपुर/आगरा/मेरठ। यूपी के पूर्वांचल में गुरुवार को मौसम बदल गया। गोरखपुर, आजमगढ़ समेत 8 जिलों में बारिश हो रही है। जौनपुर में इतनी बारिश हुई कि सड़कें तालाब बन गईं। गोरखपुर में सड़कों पर एक फीट पानी भर गया। कई बाइक फंसकर बंद हो गईं। मौसम विभाग ने आज 48 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। इधर, पहाड़ों पर हो रही बारिश से यूपी में गंगा, यमुना और शारदा समेत 10 नदियां उफान पर हैं।

80 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। सबसे ज्यादा फर्रुखाबाद में 49 गांवों में बाढ़



है। काशी में घाटों की सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया है। 100 से ज्यादा छोटे मंदिर डूब गए हैं। हरिश्चंद्र घाट पर शवदाह स्थल डूब गया है।

घाट की ऊपरी सीढ़ियों पर चिताएं जलाई जा रही हैं। लोगों को 2 से 3 घंटे तक शव का अंतिम संस्कार कराने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। कानपुर में गंगा नदी चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच गई है। 5 से ज्यादा गांवों में पानी घुस गया है। बच्चे नाव से स्कूल जा रहे हैं। उन्नाव में गंगा का पानी कॉलोनियों में घुस गया है। छतों पर लोगों की जिंदगी बीत रही है। गलियों में नावें चल रही हैं।

लखीमपुर-खीरी में शारदा नदी में अब तक 70 एकड़ जमीन समा चुकी है। गोरखपुर में 2 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। साथ ही 30-40 KM प्रति घंटे की गति से हवा चल रही है।

वहीं बारिश से सड़कें तालाब बन गईं हैं। कुछ लोगों की स्कूटी और बाइक बंद हो गई। लोग उन्हें खींचकर ले जाते दिखाई दिए। गोरखपुर में गुरुवार सुबह से ही तेज धूप निकल आई।

इसकी वजह से लोगों को उमस और गर्मी का सामना करना पड़ा। सुबह के समय ही तापमान 32 डिग्री तक पहुंच गया।

बेकाबू डंपर ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचला, 2 की मौत, तीसरा हाईवे किनारे तड़पता मिला

मुरादाबाद में हाईवे पर बिछे लाश के टुकड़े

घटना

तमसा संकेत, एजेंसी

मुरादाबाद। मुरादाबाद में बेकाबू डंपर ने बाइक सवार तीन युवकों को कुचल दिया। हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद डंपर चालक वाहन लेकर मौके से भाग गया। हादसा मूंढापांडे थाना क्षेत्र में भदासना हवाई अड्डे के मोड़ के सामने हुआ। घटना गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे की बताई जा रही है। हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दो युवकों के शव हाईवे पर बिखरे पड़े दिखाई दे रहे हैं। वहीं तीसरा युवक सड़क किनारे दर्द से तड़पता दिखाई दिया। यह दृश्य देखकर हाईवे से गुजर रहे लोगों की भीड़



जमा हो गई। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। हादसे के तुरंत बाद हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। राहगीरों ने घायल युवक को संभालने की कोशिश की और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची मूंढापांडे पुलिस ने तीनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। प्रत्यक्षदर्शी सोनू ने बताया- हम रजोड़ा गांव के रहने वाले हैं। हादसे के समय दो बाइक थीं। एक स्प्लेंडर बाइक रॉन्ग साइड से आ रही थी। दूसरी बाइक हमारे गांव रजोड़ा के लड़कों की थी। दोनों बाइक आपस में टकरा गईं। तभी पीछे से आए डंपर ने उन लोगों को कुचल दिया। डंपर चालक हादसे के बाद

एक्सपोर्ट फैक्ट्री जा रहे थे तीनों युवक

जानकारी के अनुसार रझौड़ा कन्नरदेव गांव निवासी खेमपाल, सौरभ और सूरज एक ही बाइक से मुरादाबाद स्थित एक एक्सपोर्ट फैक्ट्री में काम करने जा रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक भदासना हवाई अड्डे के कट के पास पहुंची, सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी भयानक थी कि तीनों युवक सड़क पर दूर तक उछल गए। हादसे के बाद शव करीब 25 मीटर तक हाईवे पर बिखरे पड़े रहे।

आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले ही डंपर चालक वाहन को तेज गति से भगाकर फरार हो गया।

तीन में दो की मौत

डॉक्टरों ने जांच के बाद हादसे के तुरंत बाद हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। राहगीरों ने घायल युवक को संभालने की कोशिश की और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची मूंढापांडे पुलिस ने तीनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद खेमपाल और सौरभ को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल सूरज को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। जबकि गंभीर रूप से घायल सूरज को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है।

डंपर छोड़कर भाग गया। हादसे में हमारे गांव के दो लड़कों की मौत हुई है।



- इसी बाइक पर सवार होकर तीनों युवक फैक्ट्री पर काम करने जा रहे थे।
- प्रत्यक्षदर्शी सोनू ने बताया- जिन दो लड़कों की जान गई, वो हमारे गांव के थे।

ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा में उमड़ा किसानों का सैलाब

प्रशासन की अनदेखी पर भड़के किसान

तमसा संकेत, संवाददाता

बरौली (मथुरा), 13 अगस्त। 68वें भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के राष्ट्रीय आह्वान पर गुरुवार को बरौली स्थित प्रवक्ता कैंप कार्यालय से भव्य ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लेकर अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया और विभिन्न मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। सावन मास और कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए संगठन ने 15 अगस्त के स्थान पर 13 अगस्त को यात्रा आयोजित की। किसानों ने इसे प्रशासनिक सूझबूझ और अनुशासन का परिचायक बताया। ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा बरौली से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से गुजरी। इस दौरान किसानों ने अपनी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय



समस्याओं से संबंधित ज्ञापन अधिशासी अभियंता (प्रथम) मथुरा, उपखंड अधिकारी बलदेव और नायब तहसीलदार महावन को सौंपा। इसके अलावा किसानों ने जर्जर विद्युत लाइनों की मरम्मत, बिजली बिलों में संशोधन, घरेलू उपभोक्ताओं की क्षमता वृद्धि में हो रही अनियमितताओं पर रोक लगाने तथा 220 केवी गोकुल से बरौली आने वाली 33 केवी लाइन से बलदेव के पांच फीडरों को जोड़ने के कारण उत्पन्न हो रही ब्रेकडाउन की समस्या के स्थायी समाधान की मांग उठाई।

फास्ट न्यूज

सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की आड़ में घोटाला

आगरा। आगरा नगर निगम में आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों की भर्ती की आड़ में बड़ा घोटाला हुआ है। 1000 सफाई कर्मचारियों की कागजों में भर्ती दिखाकर एक साल तक इनके नाम का नगर निगम का बजट ठिकाने लगाया गया। जबकि किसी भी वार्ड में अतिरिक्त सफाई कर्मचारी पहुंचे ही नहीं। इस पर पार्षदों ने भर्ती के नाम पर 1000 सफाई कर्मचारियों के लिए निर्धारित बजट के बंदरबांट का आरोप लगाया है।

अलीगढ़ में 20 किलो गांजा पकड़ा, 5 तस्कर गिरफ्तार

अलीगढ़। अलीगढ़ में सिविल लाइन पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 20 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1,070 रुपए, एक बाइक और एक स्कूटी भी मिली है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कामरान निवासी हमदर्द नगर, मोहित कुमार और विनय गुप्ता निवासी सासनी हाथरस, मुस्कान निवासी रामनगर बरकाती और मुरादन निवासी रजा नगर के रूप में हुई है। सभी को बुधवार को सिविल लाइन थाना क्षेत्र से पकड़ा गया।

स्वतंत्रता दिवस से पहले मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ी

मुरादाबाद। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 15 अगस्त से पहले रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने स्टेशन परिसर में सघन चेकिंग अभियान शुरू किया है। सुरक्षाकर्मी स्टेशन के प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, प्रवेश और निकास द्वार के साथ-साथ पटरियों के आसपास भी लगातार निगरानी कर रहे हैं।

कीटनाशक दवाओं के गोदाम पर छापा

गुजरात एटीएस ने की रेड, एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू

- कार्रवाई के दौरान गोदाम से जुड़े मोहन श्याम फोरमैन को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी।

तमसा संकेत, एजेंसी

मथुरा। मथुरा के बरसाना थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात गुजरात पुलिस ने एक गोदाम में छापेमारी की। यह गोदाम शराब के ठेके के पीछे स्थित बताया जा रहा है। सूचना मिली थी कि यहां गुजरात की एक कंपनी के नाम पर कथित तौर पर कीटनाशक दवा तैयार की जा रही है। मामले की जानकारी मिलने के बाद गुजरात पुलिस मथुरा पहुंची और स्थानीय पुलिस तथा औषधि विभाग की टीम को साथ लेकर कार्रवाई शुरू की। संयुक्त टीम ने गोदाम में करीब पांच घंटे तक जांच-पड़ताल की।



5 घंटे तक चली कार्रवाई

कार्रवाई के दौरान गोदाम से जुड़े मोहन श्याम फोरमैन को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। टीम यह पता लगाने में जुटी है कि गोदाम में किस कंपनी के नाम पर कौन सी दवा तैयार की जा रही थी और उसके लिए जरूरी लाइसेंस एवं अनुमति मौजूद थी या नहीं।

देर रात तक चली कार्रवाई के चलते आसपास के इलाके में भी हलचल बनी रही। नंदगांव चौकी पुलिस मौके पर मौजूद रही और सुरक्षा व्यवस्था संभाली। कार्रवाई के दौरान गोदाम से जुड़े मोहन श्याम फोरमैन को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी

गोदाम से जुड़े व्यक्ति को हिरासत में लिया

कार्रवाई के दौरान गोदाम से जुड़े मोहन श्याम फोरमैन को हिरासत में लिया गया। टीम ने उससे गोदाम में होने वाली गतिविधियों और दवा तैयार करने से संबंधित जानकारी को लेकर पूछताछ की। पुलिस और विभागीय अधिकारी यह पता लगाने में जुटे हैं कि गोदाम का संचालन किसके निर्देश पर किया जा रहा था और वहां तैयार की जा रही दवा का इस्तेमाल कहां किया जाना था। संयुक्त टीम अब बरामद दवाओं और निर्माण सामग्री की जांच कर रही है। अधिकारियों का मुख्य फोकस इस बात पर है कि तैयार की जा रही कीटनाशक दवा निर्धारित गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के अनुरूप थी या नहीं। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि दवा निर्माण की प्रक्रिया के लिए सभी जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गई थीं या नहीं। दवाओं और निर्माण सामग्री की जांच की जा रही है। मामले में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई तय की जाएगी।

हरियाली तीज पर बरसाना में प्रशासन अलर्ट, राधारानी मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर हुई समन्वय बैठक

तमसा संकेत, संवाददाता

बरसाना। आगामी हरियाली तीज पर्व को देखते हुए श्री राधारानी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रोपवे कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण समन्वय गोष्ठी आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सुरेश चंद्र रावत और अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) डॉ. अमरेश कुमार ने संयुक्त रूप से की। बैठक में श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकास मार्ग को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। तय किया गया कि श्रद्धालु श्रीजी गेट, कटारा पार्क, सुदामा चौक, दादी बाबा मंदिर, सिंगपुर गेट और सफेद छतरी मार्ग से होकर मंदिर में दर्शन के लिए प्रवेश करेंगे। दर्शन के बाद श्रद्धालु निकास द्वार से जयपुर मंदिर और थाना तिराहा मार्ग के माध्यम से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे।



अधिकारियों ने भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए संवेदनशील स्थानों पर बैरिकेडिंग कराने तथा श्रद्धालुओं के मार्गदर्शन के लिए प्रमुख स्थानों पर साइनेज बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। साथ ही चिकित्सा सुविधाओं और स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में एसडीएम गोवर्धन, नगर पंचायत बरसाना के अधिशासी अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, लाडली जी मंदिर के रिसीवर डॉ. यज्ञ पुरुष, कीर्ति मंदिर के प्रतिनिधि लक्ष्मण सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और व्यवस्था से जुड़े गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

स्वतंत्रता दिवस से पहले आईओसीएल रिफाइनरी में मॉक ड्रिल

तमसा संकेत, संवाददाता

मथुरा। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर गुरुवार को आईओसीएल मथुरा रिफाइनरी में सीआईएसएफ के नेतृत्व में मेगा संयुक्त सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान बम की सूचना और आतंकी हमले जैसी आपातकालीन परिस्थितियों का अभ्यास कर सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों को परखा गया। सीआईएसएफ के उच्चतर मुख्यालय के निर्देशानुसार सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित मॉक ड्रिल के पहले चरण में रिफाइनरी के प्रवेश द्वार संख्या-1 पर बम धमकी मिलने का परिदृश्य तैयार किया गया। सूचना मिलते ही सीआईएसएफ ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर सघन तलाशी अभियान शुरू किया। तलाशी के दौरान एक संदिग्ध लावारिस लंच बॉक्स बरामद हुआ। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की बम निरोधक दस्ता (बीडीडीएस) और डॉग स्क्वाड टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच में विस्फोटक सामग्री होने की



पुष्टि होने पर उसे सुरक्षित तरीके से निष्प्रभावी कर दिया गया। मॉक ड्रिल के दूसरे चरण में शहीद होशियार सिंह गेट पर हथियारबंद आतंकवादियों के रिफाइनरी परिसर में प्रवेश करने की स्थिति का अभ्यास किया गया। सूचना मिलते ही सीआईएसएफ की क्विक रिस्पांस टीम, असॉल्ट पार्टी, कॉर्डन पार्टी और रेस्क्यू पार्टी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आतंकवादियों को निष्प्रभावी कर दिया और पूरे क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया। अभ्यास के दौरान एक घायल कर्मचारी को सुरक्षित बाहर निकालकर एम्बुलेंस के माध्यम से प्राथमिक उपचार के लिए भेजने की प्रक्रिया का भी प्रदर्शन किया गया।

8 घंटे में बरामद किया 10 लाख कीमती सामान, सीसीटीवी की मदद से पकड़ा सुराग, फरियादी ने जताया आभार

स्टेशन पर छूटा कैमरे से भरा बैग

तमसा संकेत, एजेंसी

आगरा। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर GRP की सक्रियता और तत्परता एक बार फिर यात्रियों के लिए मिसाल बनी है। दिल्ली निवासी संदीप कुमार का करीब 10 लाख रुपये कीमत के कैमरे और महंगे गैजेट्स से भरा बैग स्टेशन पर कहीं छूट गया था। बैग गायब होने की जानकारी मिलते ही उन्होंने GRP को सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम तत्काल तलाश में जुट गई और करीब आठ घंटे की लगातार कार्रवाई के बाद बैग बरामद कर उसके मालिक को सुरक्षित सौंप दिया।GRP टीम ने लगातार कई घंटे तक अभियान चलाया। संभावित स्थानों पर जांच और CCTV फुटेज के आधार पर की गई कार्रवाई के बाद करीब आठ घंटे में पुलिस को बैग का सुराग मिल गया। टीम ने बैग को बरामद कर अपने कब्जे में लिया और उसकी जांच की।



बताया गया कि संदीप कुमार आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान भीड़भाड़ के बीच उनका कैमरा बैग कहीं छूट गया। बैग में प्रोफेशनल कैमरा, कई लेंस और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रखे थे। पूरे सामान की अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपये बताई जा रही है। इतने महंगे उपकरणों से भरा बैग गायब होने की जानकारी मिलने के बाद संदीप कुमार की चिंता बढ़ गई।

सूचना मिलते ही जीआरपी ने शुरू की तलाश

बैग खोने की सूचना मिलते ही आगरा कैंट GRP सक्रिय हो गई। प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले स्टेशन परिसर में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली गई। पुलिस ने अलग-अलग कैमरों की रिकॉर्डिंग के जरिए यह पता लगाने का प्रयास किया कि बैग आखिरी बार कहां और किस स्थान पर दिखाई दिया था।

CCTV फुटेज की जांच के दौरान पुलिस टीम को बैग के संबंध में महत्वपूर्ण सुराग मिला। फुटेज में बैग एक यात्री के पास जाता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद GRP ने स्टेशन परिसर के विभिन्न हिस्सों के साथ-साथ प्लेटफॉर्म, वेटिंग रूम और आसपास के इलाकों में तलाश तेज कर दी।

कैमरे और सभी गैजेट्स मिले सुरक्षित

बैग की जांच करने पर उसमें रखे प्रोफेशनल कैमरे, लेंस और अन्य महंगे गैजेट्स सुरक्षित मिले। सामान सुरक्षित मिलने के बाद पुलिस ने आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करते हुए बैग को उसके वास्तविक मालिक संदीप कुमार के सुपुर्द कर दिया। करीब 10 लाख रुपये कीमत का सामान वापस मिलने पर संदीप कुमार ने GRP टीम का आभार जताया। उन्होंने पुलिस की तत्परता और ईमानदारी की सराहना करते हुए कहा कि इतनी कीमती चीजें वापस मिल जाएंगी, इसकी उन्हें उम्मीद कम थी। समय रहते पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से उनका बड़ा आर्थिक नुकसान होने से बच गया।

यात्रियों से सामान संभालकर रखने की अपील

GRP प्रभारी ने यात्रियों से अपील की है कि रेलवे स्टेशन और ट्रेन में सफर के दौरान अपने सामान की विशेष निगरानी रखें। खासतौर पर महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कैमरा, लैपटॉप और अन्य कीमती सामान को लापरवाही से न छोड़ें। किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि नजर आने पर तत्काल GRP को सूचना दें। GRP अधिकारियों के मुताबिक रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर पुलिस लगातार सतर्क रहती है।

पृष्ठ 01 का शेष...

लोकसभा 1...

मानसून सत्र में राज्यसभा की बैठकें भी लोकसभा के बराबर रहीं और 114 घंटे कार्यवाही होनी थी, लेकिन राज्यसभा में लगभग 37 घंटे 24 मिनट काम हुआ। यानी करीब 76 घंटे 36 मिनट कम कार्यवाही हुई। राज्यसभा की कार्यवाही गुरुवार को 1:06 घंटे चली। सदन में माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026 पास हुआ। इसके बाद वंदे मातरम हुआ और सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली में छात्रों पर हुई लाठीचार्ज मामले में अमित शाह के बयान की मांग को लेकर राज्यसभा में खड़गे और रिजिजू के बीच तीखी बहस हुई।खड़गे ने सभापति से गृहमंत्री को सदन में बुलाने के लिए आदेश देने की अपील की। लोकसभा में गुरुवार को कार्यवाही शुरू होते ही वंदे मातरम का गान हुआ। इसके बाद कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।

यूपी में सपा सरकार...

राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव ने कहा, "इस सरकार ने हर सेक्टर में बहुत लूट-खसोट की है ये सभी भ्रष्ट हैं। ये रिश्वत लेते हैं और कोई काम भी नहीं करते। तो, हमें उन्हें (भाजपा) हराना है और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। फिर कहा कि आजम खान को इस पर पीछे से किसी ने कहा कि रक्षा मंत्री बनाना है तो उन्होंने कहा रक्षा मंत्री बनने से पहले उन्हें राज्य का गृह मंत्री बनाएंगे।" जगतार सिंह हवारा को मिल सकती है पैरोल, CM मान के बाद रवनीत सिंह बिट्टू भी मिले राज्यपाल से रामपुर शिवपाल सिंह यादव ने कहा, "हमें उन्हें हराना है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है।" आगे शिवपाल ने प्रशासन पर आरोप लगाए और कहा कि आजम खान के साथ जेल में बहुत जुल्म हो रहा है। उन्होंने कहा इतने बड़े नेता को जमीन पर लिटाया जा रहा। आगे कहा, "मैं बस यह कहना चाहता हूँ कि आजम खान 10 बार विधायक और दो बार सांसद रहे हैं, जबकि अब्दुल्ला आजम दो बार विधायक रहे हैं, और उनकी पत्नी भी विधायक और राज्यसभा सदस्य रह चुकी हैं। इतने सारे पदों पर रहने, वरिष्ठ नेता और जन-प्रतिनिधि होने के बावजूद, उनके खिलाफ़ कई मामले दर्ज हैं, जिनमें कई आपराधिक आरोप भी शामिल हैं।" आगे उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनते ही सभी जुल्मों का बदला लिया जाएगा और अत्याचार करने वाले अधिकारियों और षड्यंत्रकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिवपाल ने कहा कि आजम खान ने जेल से संदेश दिया है कि अखिलेश यादव पूरे प्रदेश का दौरा करें और जनता के बीच जाकर सपा सरकार को लेकर माहौल बनाएं। उन्होंने कहा कि आजम ने इतने जुल्म के बाद भी हिम्मत नहीं हारी है वह मजबूती से खड़े हैं। वह पूरी तरह सपा और अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं।

गुटखा-तंबाकू...

राज्य के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू या निकोटीन वाले दूसरे संबंधित उत्पादों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने इन उत्पादों के निर्माण, भंडारण, ले जाने-पहुंचाने, वितरण और बिक्री पर एक साल के लिए रोक लगा दी है. मीडिया में छपी खबर के मुताबिक, विभाग ने 10 अगस्त को इस संबंध में अधिसूचना जारी की. इसमें कहा गया है कि यह रोक अधिसूचना जारी होने की तारीख से एक साल तक लागू रहेगी. यानी कर्नाटक में इन प्रतिबंधित उत्पादों के कारोबार से जुड़े लोगों के लिए अब मुश्किल बढ़ सकती है. इस फैसले की खास बात यह है कि इसका दायरा काफी बड़ा रखा गया है. आम तौर पर गुटखा या पान मसाला पर रोक की बात सुनते ही लोगों का ध्यान दुकानों और बिक्री पर जाता है. लेकिन कर्नाटक के इस आदेश में केवल बेचने वालों को निशाना नहीं बनाया गया है. तंबाकू या निकोटीन वाले उत्पाद बनाने वालों पर भी रोक है. इन्हें गोदाम या किसी दूसरी जगह पर रखने वालों की भी जांच होगी. इसके अलावा एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने और बाजार में बांटने वालों को भी प्रतिबंध के दायरे में रखा गया है. कर्नाटक सरकार ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू-निकोटीन वाले उत्पादों पर कितने समय के लिए सरकार ने इस बार पूरी सप्लाई चेन को जांच के दायरे में रखा है. इसका मतलब है कि अगर कोई प्रतिबंधित उत्पाद बाजार में पहुंच रहा है, तो विभाग केवल दुकान तक पहुंचकर जांच नहीं करेगा.. आदेश में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है. कुछ ऐसे उत्पाद भी जांच के दायरे में आ सकते हैं जिन्हें अलग-अलग पैकेट में बेचा जाता है, लेकिन ग्राहक उन्हें आसानी से मिलाकर इस्तेमाल कर सकता है. यानी केवल अलग-अलग पैक में सामान बेचने से प्रतिबंध से बचने की कोशिश नहीं की जा सकेगी. अगर अंतिम उत्पाद में तंबाकू या निकोटीन मौजूद है या उत्पादों को मिलाकर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो विभाग ऐसे मामलों की भी जांच करेगा. सरकार ने इस अभियान में आम लोगों से भी सहयोग मांगा है. खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने अपील की है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रतिबंधित तंबाकू या निकोटीन वाले उत्पादों के बनने, बिकने या बांटे जाने की जानकारी मिलती है तो वह संबंधित अधिकारियों को सूचना दे. विभाग का कहना है कि लोगों की भागीदारी से प्रतिबंधित उत्पादों की उपलब्धता रोकने में मदद मिलेगी. सरकार ने इसे स्वस्थ और नशा-मुक्त कर्नाटक की दिशा में उठाया गया कदम बताया है.पूरे कर्नाटक में शुरू हुई जांच अधिसूचना जारी होने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने राज्यभर में कार्रवाई तेज कर दी है. फूड सेफ्टी अधिकारियों की निगरानी में जांच अभियान चलाया जा रहा है. इसका मकसद प्रतिबंधित तंबाकू और निकोटीन वाले उत्पादों को बाजार में पहुंचने से रोकना है. अधिकारी ऐसे स्थानों की जांच कर सकते हैं जहां प्रतिबंधित सामान बनाए जाने, रखे जाने या बेचे जाने की जानकारी मिलती है. सरकार की कोशिश है कि प्रतिबंध केवल कागज पर न रहे, बल्कि बाजार में भी इसका असर दिखाई दे.

यूपी की महिलाओं...

इसमें हर साल बढ़ोतरी भी होगी। अखिलेश ने पूछा- भाजपा सरकार पिछले 10 साल में महिलाओं को 50 हजार रुपए सालाना दे सकती थी, लेकिन नहीं दिया। सरकार ने महिलाओं के हक-के हजारों करोड़ रुपए प्रचार पर खर्च कर दिए। 50 हजार रुपए सालाना के हिसाब से पिछले 10 साल में महिलाओं के हिस्से का 5 लाख रुपए 'खा लिया' गया। अब सिर्फ 20 हजार का जुमला परोसा जा रहा है। अखिलेश ने इसे 96:4 का अनुपात बताते हुए भ्रष्टाचार का 'सुपर रिकॉर्ड' करार दिया। अखिलेश ने कहा- अगर 15 लाख रुपए वाले पुराने जुमले को छोड़ भी दें और 20 हजार दे भी दें, तो भी जनता का भाजपा सरकार पर 4,80,000 रुपए बकाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनाक्रोश के डर से भाजपा के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक भूमिगत हो गए हैं।

मंदिर में चोरी और बच्चों पर हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा के पास न नैतिकता बची है, न साहस, इसलिए वे पैसे का सहारा ले रहे हैं। पोस्ट के आखिर में अखिलेश यादव ने लिखा- हम 40000 से करेंगे शुरुआत जिसमें 'बढ़ोतरी' होगी हर साल! गौरतलब है कि हाल ही में यूपी सरकार की ओर से 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता योजना की चर्चा हो रही है। इसमें कुल 50 हजार रुपए तक की मदद का प्रस्ताव बताया जा रहा है, जिसमें चुनाव से पहले 20 हजार की पहली किस्त दिए जाने की संभावना जताई गई है। अखिलेश यादव पहले भी कई मौकों पर महिलाओं को सालाना 40 हजार रुपये देने का वादा कर चुके हैं।

198 रन पर ऑलआउट, स्टीव स्मिथ की फिफ्टी, हसन महमूद ने लिए 6 विकेट

बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का सबसे कम टेस्ट स्कोर 198 रन पर ऑलआउट

प्रदर्शन

नई दिल्ली, एजेंसी

बांग्लादेश के खिलाफ डार्विन में खेले जा रहे पहले टेस्ट की पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया 198 रन पर ऑलआउट हो गई। यह टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का सबसे कम स्कोर है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया का सबसे कम स्कोर 217 रन था। यह 2017 में मीरपुर टेस्ट में बना था।

जवाब में पहले दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने 1 विकेट खोकर 96 रन बनाकर लिए हैं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत खराब रही। लंच तक टीम ने 74 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद स्टीव स्मिथ ने पारी संभालने की कोशिश की, लेकिन उनके आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के आखिरी चार विकेट भी जल्दी गिर गए।



बांग्लादेश के हसन महमूद 6 विकेट लेने के बाद सेलिब्रेट करते हुए।

बांग्लादेश की ओर से हसन महमूद ने करियर का बेस्ट प्रदर्शन करते हुए 17 ओवर में 55 रन देकर 6 विकेट लिए। तस्कीन अहमद और इबादत हुसैन को 2-2 विकेट मिले।

ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका हसन महमूद ने दिया। उन्होंने जेक वेदराल्ड को 23 रन पर आउट किया। इसके बाद अगले ही ओवर में ट्रैविस हेड को भी पवेलियन भेज दिया।

मार्नस लाबुशेन सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कैमरन ग्रीन 13 रन बना सके। इस तरह लंच तक ऑस्ट्रेलिया ने 74 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे। दूसरे सेशन में स्मिथ और कैरी ने पारी को संभाला। दोनों ने 55 रन जोड़े, लेकिन कैरी के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया की पारी फिर लड़खड़ा गई। ब्यू वेबस्टर 12, पैट कमिंस 9 और मिचेल स्टार्क 1 रन बनाकर आउट हुए।

स्मिथ ने 71 रन की पारी खेली

ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्टीव स्मिथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने 109 गेंदों पर 71 रन बनाए। उनकी पारी में 7 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। स्मिथ ने एलेक्स कैरी के साथ पांचवें विकेट के लिए 55 रन की साझेदारी की। यह ऑस्ट्रेलिया की पारी की सबसे बड़ी साझेदारी रही। कैरी 19 रन बनाकर आउट हुए।

बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के सबसे कम टेस्ट स्कोर

रैंक	स्कोर	मैदान	तारीख
1	198	डार्विन	13 अगस्त 2026
2	217	मीरपुर	27 अगस्त 2017
3	244	मीरपुर	27 अगस्त 2017
4	269	फतुल्लाह	9 अप्रैल 2006
5	307/7	फतुल्लाह	9 अप्रैल 2006

आकाशदीप-मुकेश की डीएसपी नौकरी पर पांच साल की शर्त

आकाशदीप-मुकेश को 5 साल क्रिकेट खेलना होगा

पटना, एजेंसी



भारतीय क्रिकेट में तेज गेंदबाज आकाश दीप और मुकेश कुमार को बिहार पुलिस में DSP बनाए जाने के बाद अब सरकारी सेवा को लेकर नई शर्त सामने आई है।

गृह विभाग की अधिसूचना के मुताबिक, दोनों क्रिकेटरों को 5 साल का बॉन्ड भरना होगा। इस अवधि में उन्हें सक्रिय क्रिकेट खिलाड़ी के तौर पर टूर्नामेंट में हिस्सा लेते रहना अनिवार्य होगा।

उन्हें विभिन्न क्रिकेट टूर्नामेंट में सक्रिय खिलाड़ी के तौर पर हिस्सा लेना होगा। यदि वे बॉन्ड में तय शर्तों का पालन नहीं करते हैं या क्रिकेट खेलना पूरी तरह छोड़ देते हैं, तो उनकी सरकारी सेवा पर असर पड़ सकता है।

बिहार सरकार के 2026 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ़ आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्सपर्सन रेगुलेशन के तहत, नियुक्त खिलाड़ियों को नौकरी जॉइन करने की तारीख से पांच साल तक एक्टिव खिलाड़ी के तौर पर कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना होगा। सरकारी नौकरी में रहते हुए खेलों में अपनी भागीदारी बनाए रखना जरूरी है। इसका मतलब है कि अगर कोई खिलाड़ी तय शर्तों के मुताबिक खेल कॉम्पिटिशन में एक्टिव रूप से हिस्सा नहीं ले पाता है, तो उसकी उसकी सेवा स्थायी किए जाने में समस्या आ सकती है।

बिहार सरकार की 'मेडल लाओ, नौकरी पाओ' योजना के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य और देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में नियुक्त किया जा रहा है।

अफगानिस्तान ने आयरलैंड को 42 रन से हराया 16 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा

अटल-जादरान में 231 रन की साझेदारी

नई दिल्ली, एजेंसी



अफगानिस्तान ने बुधवार को बेलफास्ट में आयरलैंड पर 42 रन की जीत दर्ज की। टीम ने 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली। सीरीज का आखिरी मैच 15 अगस्त को बेलफास्ट में ही खेला जाएगा। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 343 रन बनाए। सेदिकुल्लाह अटल ने 143 और इब्राहिम जादरान ने 107 रन बनाए। जवाब में आयरलैंड 48 ओवर में 301 रन पर ऑलआउट हो गई। एंडी बालबर्नी ने 109 और कर्टिस कैम्फर ने 84 रन बनाए। अफगानिस्तान से यमीन अहमदजई ने 4 विकेट और राशिद खान ने 3 विकेट लिए। आयरलैंड के मैकडोनफ ने 3 और गेविन होई ने 2 विकेट चटकाए। अटल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

अफगानिस्तान को शुरुआत में ही झटका लगा। पिछले मैच के टॉप स्कोरर रहमानुल्लाह गुरबाज दूसरे ओवर में आउट हो गए। इसके बाद अटल और जादरान ने दूसरे विकेट के लिए 231 रन की साझेदारी करके पारी संभाली। यह वनडे में अफगानिस्तान के लिए इस विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी है।

दोनों ने 16 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। यह रिकॉर्ड करीन सादिक और मोहम्मद शहजाद के नाम था, जिन्होंने स्कॉटलैंड के खिलाफ 218 रन की साझेदारी की थी। अटल ने अपने 25वें जन्मदिन पर शतक लगाया। उन्होंने पारी के बीच के ओवरों में समझदारी से बल्लेबाजी की और जब भी पारी धीमी पड़ने लगी, खासकर स्पिन के खिलाफ बाउंड्री लगाकर फिर से गति बढ़ाई। अटल ने लगातार बाउंड्री लगाकर गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। वे 150 रन के करीब पहुंचते दिख रहे थे, लेकिन लॉन्ग ऑन पर गलत टाइमिंग वाले शॉर्ट पर आउट हो गए।

जादरान ने भी अटल का पूरा साथ दिया। उन्होंने वनडे करियर का 7वां शतक लगाया। जादरान की पारी में 11 चौके और एक छक्का शामिल रहा।

बड़े लक्ष्य के जवाब में आयरलैंड ने धीमी शुरुआत की। शुरुआती पहले 8 ओवर में टीम केवल 25 रन बना सकी।

10 हार के बाद भी गंभीर के समर्थन में मिश्रा

कहा-कोच के साथ खिलाड़ियों को भी जिम्मेदारी लेनी होगी, रेड-बॉल क्रिकेट को देना होगा समय

नई दिल्ली, एजेंसी



भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर के लिए अब तक का सफर आसान नहीं रहा है। टेस्ट में 10 हार के बाद भी पूर्व भारतीय लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने उनका समर्थन किया है। मिश्रा ने कहा कि इस दौर के लिए सिर्फ कोच को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। उनके मुताबिक, खिलाड़ियों को भी ज्यादा जिम्मेदारी लेने की जरूरत है और गंभीर को रेड-बॉल क्रिकेट में समय मिलना चाहिए। व्हाइट-बॉल क्रिकेट में टीम इंडिया ने शानदार नतीजे दिए हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन को लेकर सवाल उठे हैं। इसी वजह से टीम के कोचिंग सेटअप और खासतौर पर गंभीर की भूमिका पर चर्चा होती रही है।

गंभीर के कार्यकाल में न्यूजीलैंड ने भारत को घरेलू मैदान पर 3-0 से हराया, जबकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत को घर में 2-0 की हार झेलनी पड़ी।

भारत ने ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 3-1 से गंवाई। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज 2-2 से बराबर रही। मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में भी भारत की स्थिति फिलहाल मजबूत नहीं है। ऐसे में आने वाली टेस्ट सीरीज टीम के लिए बेहद अहम होने वाली हैं।

मिश्रा का मानना है कि गंभीर को टेस्ट क्रिकेट में अपनी योजनाएं लागू करने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, उन्हें रेड-बॉल क्रिकेट में समय दीजिए। उन्हें टीम के नए खिलाड़ियों को समझाने की जरूरत है। कोच और खिलाड़ी की भूमिका का फर्क बताते हुए मिश्रा ने कहा, कोच का काम मानसिक पहलुओं और स्किल्स पर काम करना है, लेकिन खिलाड़ियों को मैदान पर प्रदर्शन करना होता है। उन्होंने कहा, आपको दबाव लेना होता है, परिस्थितियों को समझना होता है। आपको समय बिताना होता है और परिस्थिति, खिलाड़ी, गेंदबाज और विकेट के अनुसार अपना खेल बदलना होता है।

> **अपनी बात समझाने के लिए मिश्रा ने राहुल द्रविड़ का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा, राहुल द्रविड़ को खुद को स्थापित करने में 1-1.5 साल लगे थे। उसके बाद प्रदर्शन में सुधार आया। मिश्रा के मुताबिक, इंटरनेशनल क्रिकेट में जगह मिलना ही काफी नहीं है। खिलाड़ियों को हालात के हिसाब से अपना खेल बदलना भी आना चाहिए।**

मिश्रा ने कोच को दोष देने से इनकार किया

लगातार खराब नतीजों के बीच अलग-अलग फॉर्मेट के लिए अलग कोच रखने की चर्चा भी सामने आती रही है। मिश्रा इस सोच से पूरी तरह सहमत नहीं हैं।

मिश्रा ने कहा, कोच के लिए यह मुश्किल है। मुझे लगता है कि खिलाड़ियों को ज्यादा जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। कई सालों से एक कोच सभी फॉर्मेट के लिए रहा है। किसी भी कोच को समय देना जरूरी है।

उन्होंने आगे कहा, टेस्ट मैचों में हमारे पास कम अनुभव वाले नए खिलाड़ी हैं। कोच और खिलाड़ियों को साथ मिलकर काम करने और विकसित होने में समय लगता है।

मनोरंजन

2007 में रिलीज हुई थी आवारापन श्रिया सरन थीं फिल्म की लीड एक्ट्रेस

19 साल बाद आवारापन की 'आलिया' का शॉकिंग खुलासा

नई दिल्ली। निर्देशक मोहित सूरी के डायरेक्शन में साल 2007 में अभिनेता इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन को रिलीज किया गया था। इस मूवी में अभिनेत्री श्रिया सरन ने आलिया का मुख्य किरदार निभाया था। बेशक आज आवारापन एक कल्ट मूवी मानी जाती है, लेकिन उस वक्त ये फिल्म फ्लॉप रही थी। इस बीच आवारापन एक्ट्रेस श्रिया सरन ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है और बताया है कि आवारापन के फ्लॉप होने से उनके साथ इंडस्ट्री में भेदभाव हुआ था।



फिल्म आवारापन फिलहाल अपने सीक्वल को लेकर चर्चा में बनी हुई है, जिसके जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। आवारापन 2 (Awarapan 2) से पहले अभिनेत्री श्रिया सरन ने पिंकविला को लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है और कई राज खोल हैं, उन्होंने बताया है- जब आवारापन बन रही थी तो उस वक्त मैं काफी एक्साइटेड थी। मुझे लगा कि ये मूवी दर्शकों को काफी पसंद आएगी और हिट होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हमारी मूवी असफल रही। मुझे लगता है कि उस वक्त आवारापन अपने समय से आगे की फिल्म थी। बेशक मूवी को सफलता नहीं मिली, लेकिन ये कई अवॉर्ड शो में नॉमिनेट हुई थी। लेकिन मुझे हैरानी तब हुई, जब किसी भी अवॉर्ड शो से मुझे न्योता नहीं मिला। एक तरह से मेरे साथ भेदभाव सा हुआ था, जिससे मुझे काफी बुरा लगा था। लेकिन खैर हर किसी के जीवन में ऐसा दौर आता है। अच्छी बात ये है कि अब आवारापन 2 आ रही है और इसको लेकर जो क्रेज दिखाई दे रहा है, वह वाकई आनंद पहुंचा रहा है। इस तरह से श्रिया सरन ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर हैरान करने वाला खुलासा किया है। मालूम हो कि आवारापन 2 को शुक्रवार 14 अगस्त 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।



> **बात की जाए श्रिया सरन की अपकमिंग मूवी के बारे में तो आने वाले समय वह अजय देवगन की सस्पेंस थ्रिलर फ्रेंचाइजी दृश्यम 3 में अहम भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। जिसको 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। इससे पहले श्रिया की इस फ्रेंचाइजी की दोनों मूवीज हिट साबित हुई हैं।**

चिरंजीवी को देख इन्फ्लुएंसर पोटी मामा हुए भावुक पैरों में झुककर रोने लगे

चोट के बावजूद भतीजे वरुण ने चिरंजीवी के पैर छुए

नई दिल्ली। फिल्म कोरियन कनकराजू के एक इवेंट में फिल्म के एक्टर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पोटी मामा स्टेज पर भावुक होकर रो पड़े।

उन्होंने बताया कि वह कई सालों से अपने आइडल चिरंजीवी से मिलने का सपना देख रहे थे। भावुक होकर वह ऑडियंस में बैठे चिरंजीवी के पास पहुंचे और उनके पैर छूकर गिर पड़े। चिरंजीवी ने उन्हें तुरंत उठाया और गले लगा लिया। इसके बाद उन्होंने पोटी मामा को अपने पास फ्रंट रो में बैठाया और उनके साथ समय बिताया। चिरंजीवी ने उन्हें एक तस्वीर भी गिफ्ट की।

बता दें कि 11 अगस्त को हैदराबाद में फिल्म की ग्रैंड 'मेगा ब्लॉकबस्टर सक्सेस सेलिब्रेशंस' आयोजित हुई थी। इसमें मेगास्टार चिरंजीवी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। इसी इवेंट से फिल्म के लीड एक्टर और चिरंजीवी के भतीजे वरुण तेज का वीडियो भी सामने आया। इसमें वरुण स्टेज पर अपने चाचा के पैर छूते नजर आए। खास बात यह है कि पैर में चोट के बावजूद वह झुककर चिरंजीवी का आशीर्वाद लेने पहुंचे। वीडियो में चिरंजीवी उन्हें संभालते हुए भी नजर आ रहे हैं। वरुण तेज की यह सादगी और परिवार के प्रति सम्मान सोशल मीडिया पर चर्चा में है। बता दें कि वरुण तेज को हाल ही में उनकी अपकमिंग फिल्म 'भारी' के लिए वॉलीबॉल की प्रैक्टिस करते समय घुटने में चोट लग गई थी। वरुण तेज मुख्य भूमिका वाली फिल्म 'कोरियन कनकराजू' एक तेलुगु हॉरर-कॉमेडी है। फिल्म का निर्देशन मेरलपाका गांधी ने किया है। इसमें रितिका नायक और सत्या भी अहम किरदारों में हैं। फिल्म 7 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। 38 करोड़ के बजट वाली फिल्म 'कोरियन कनकराजू' ने 6 दिन में दुनिया भर में 25.54 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है।



33 साल पहले आया था दूरदर्शन का आईकॉनिक देशभक्ति गीत

नई दिल्ली। देशभक्ति गीत हमेशा से सिनेप्रेमियों की फेवरेट रहे हैं। समय-समय पर हिंदी सिनेमा की तरफ देश प्रेम को जगाने वाले एक से बढ़कर एक सॉन्ग को रिलीज किया गया है। लेकिन ऐसा गाना ऐसा भी है, जो पिछले 33 सालों से स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति की भावना जगता आ रहा है। साथ ही ये भारतवासियों में एकता का प्रतीक भी माना जाता है।

इस गाने को सिनेमा जगत के 4 अलग-अलग गायकों ने अपनी आवाज दी थी और इसमें कई फिल्मी सितारे भी मौजूद रहे। खास बात ये थी इस गीत को सीधा राष्ट्रीय टीवी चैनल दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था। 90 का दशक हिंदी सिनेमा के गोल्डन एरा के तौर पर याद किया जाता है। बड़े पर्दे पर फिल्मों के अलावा इस दौर में दूरदर्शन एकमात्र मनोरंजन का प्रमुख साधन माना जाता था। साल 1993 में दूरदर्शन पर एक ऐसा देशभक्ति गीत रिलीज किया गया था, जिसे आज कालजयी माना जाता है।

अजय देवगन से रिप्लेस होने पर आया अनूप सोनी का रिएक्शन

लोग मुझे क्राइम पेट्रोल के लिए याद रखेंगे

नई दिल्ली। टीवी का सबसे पॉपुलर क्राइम शो 'क्राइम पेट्रोल' (Crime Patrol) नए सीजन के साथ टीवी पर लौटने की तैयारी में है, लेकिन इस बार नए होस्ट के साथ। क्राइम पेट्रोल को अब अनूप सोनी (Anup Soni) की जगह अजय देवगन (Ajay Devgn) होस्ट करने वाले हैं।

हाल ही में, क्राइम पेट्रोल (Crime Patrol New Host) के नए होस्ट की अनाउंसमेंट हुई। डेढ़ दशक तक दर्शक जिसकी आवाज में 'सावधान रहें, सतर्क रहें' सुना करते थे, अब वह सुनाई नहीं देगी। अब अजय देवगन दर्शकों को सावधान और सतर्क करेंगे। जब तक मेरे करियर में 'क्राइम पेट्रोल' से भी बड़ा कुछ नहीं आ जाता, तब तक मैं चाहे कितना भी दूसरा काम क्यों न करूं, लोग मुझे 'क्राइम पेट्रोल' के लिए ही याद रखेंगे। 'क्राइम पेट्रोल' से पहले लोग मुझे 'बालिका वधू' के लिए पहचानते थे, लेकिन जब 'क्राइम पेट्रोल' आया, तो लोग 'बालिका वधू' को भूल गए।



अनूप सोनी ने वैरायटी को दिए इंटरव्यू में अजय देवगन के नए होस्ट बनने पर बात की। उन्होंने कहा, 'मैं अजय देवगन का बहुत बड़ा फैन हूं और मुझे प्रकाश झा की फिल्मों 'गंगाजल' और 'अपहरण' में उनके साथ काम करने का मौका भी मिला है। मुझे यकीन है कि वह शो में अपना अलग अंदाज और नजरिया लेकर आएंगे। मैं नए सीजन के लिए पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं। बात करें वर्क फ्रंट की तो अनूप सोनी भले ही 'क्राइम पेट्रोल' से बाहर हो गए हैं, लेकिन उनके पास लाइन में एक वेब सीरीज और फिल्म है। वह जल्द ही बड़े पर्दे पर अलग किरदार में धमाल मचाते हुए नजर आएंगे।

रिप्लेस होने पर अनूप सोनी का रिएक्शन

करीब डेढ़ दशक तक क्राइम शो को होस्ट करने वाले अनूप सोनी ने एक हालिया इंटरव्यू में अजय देवगन से रिप्लेस होने पर पहली बार रिएक्शन दिया है। एएनआई के साथ बातचीत में अनूप सोनी ने कहा कि लोग हमेशा उन्हें इस शो के लिए याद रखेंगे।



जापान बोला- ये हमारा हिस्सा ■ 80 साल से 4 द्वीपों को लेकर दोनों में विवाद

पुतिन पहली बार जापान के दावे वाले कुरील आइलैंड पहुंचे

दौरा

- रूस और जापान में 4 द्वीपों को लेकर विवाद
- रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव 2010 में कुरील द्वीपों का दौरा करने वाले पहले रूसी राष्ट्रपति बने थे।
- दिमित्री मेदवेदेव बाद में प्रधानमंत्री बने। तब एक बार फिर से वे अगस्त 2010 में कुरील द्वीप समूह के इतुरुप द्वीप के दौरे पर पहुंचे थे।



मॉस्को/टोक्यो, एजेंसी

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को पहली बार जापान के दावे वाले विवादित कुरील द्वीप समूह का दौरा किया। क्रेमलिन ने पुतिन के दौरे का वीडियो जारी किया। उन्होंने कुरील द्वीप पर एक फिश प्रोसेसिंग प्लांट का दौरा किया। पुतिन की इस यात्रा के बाद जापान ने कड़ा विरोध जताया और कहा कि यह इलाका उसका हिस्सा है। रूस और जापान के बीच प्रशांत महासागर में 4 द्वीपों को लेकर 80 साल से विवाद है। जापान इसे नॉर्दर्न टेरिटरीज कहता है जबकि रूस इन्हें कुरील आइलैंड ग्रुप का हिस्सा मानता है। रूस और जापान के बीच प्रशांत महासागर में स्थित चार द्वीपों को लेकर विवाद है। जापान इन्हें 'नॉर्दर्न टेरिटरीज' (उत्तरी क्षेत्र) कहता है, जबकि रूस इन्हें कुरील द्वीप समूह का हिस्सा मानता है।द्वितीय विश्व युद्ध के आखिरी दिनों में 1945 में सोवियत संघ ने इन द्वीपों पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद यहां रहने वाले करीब 17 हजार जापानी नागरिकों को वहां से हटा दिया गया। कब्जे के बाद सोवियत संघ ने यहां हवाई और नौसैनिक अड्डे बनाए। प्रशांत महासागर में रणनीतिक स्थिति होने की वजह से इन द्वीपों का सैन्य महत्व लगातार बढ़ता गया। आज भी रूस यहां बड़ी संख्या में सैनिक और आधुनिक सैन्य उपकरण तैनात रखता है।



■ राष्ट्रपति पुतिन ने बुधवार को कुरील आइलैंड के इतुरुप द्वीप पर एक फिश प्रोसेसिंग प्लांट का दौरा किया।

> द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ज्यादातर देशों ने आपस में शांति संधि (पीस ट्रीटी) पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन कुरील द्वीपों के विवाद की वजह से रूस और जापान आज तक ऐसा नहीं कर सके हैं।

दोनों देशों में नाम लगभग एक जैसे

खास बात यह है कि इन विवादित द्वीपों के नाम दोनों देशों में लगभग एक जैसे हैं। रूस इन्हें कुनाशिर, इतुरुप, शिकोतान और हाबोमाई कहता है, जबकि जापान इन्हें कुनाशिरी, एतोरोफू, शिकोतान और हाबोमाई के नाम से जानता है। इन चारों द्वीपों पर करीब 20 हजार लोग रहते हैं। यहां बहुत ठंड पड़ती है, लेकिन सोना-चांदी जैसे खनिज और मछलियों के बड़े भंडार होने की वजह से इन द्वीपों की आर्थिक अहमियत काफी ज्यादा है।



■ पुतिन ने कैवियार का स्वाद लिया। यह स्टर्जन मछली के अंडों से बनता है और इसे दुनिया के सबसे महंगे खाद्य पदार्थों में गिना जाता है।

रूस 2 द्वीप देने का तैयार हुआ, जापान नहीं माना

1956 में सोवियत संघ और जापान के बीच राजनयिक संबंध बहाल होने के बाद विवाद सुलझाने की कोशिश शुरू हुई। उस समय सोवियत नेता निकिता ख्रुश्चेव ने शांति समझौते के बदले शिकोतान और हाबोमाई द्वीप जापान को लौटाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन जापान चार से कम मानने को तैयार नहीं था। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद भी रूस और जापान के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। 2010 में तत्कालीन रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव इन विवादित द्वीपों का दौरा करने वाले पहले रूसी राष्ट्रपति बने। इसके बाद रूस ने यहां अपनी सैन्य मौजूदगी और मजबूत की, जबकि जापान लगातार अपना दावा दोहराता रहा। यूक्रेन युद्ध के बाद दोनों देशों के रिश्ते और खराब हो गए। अब पुतिन का यह दौरा इन विवादित द्वीपों पर रूस के दावे को फिर से मजबूत करने के मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है।

फास्ट न्यूज

भारतीय छात्रों के लिए अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट में देरी

वाशिंगटन। अमेरिका में फॉल एकेडमिक सीजन शुरू होने में अब कुछ ही हफ्ते बचे हैं, ऐसे में भारतीय छात्रों सहित अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए समय पर छात्र-वीजा अपॉइंटमेंट न मिलना एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है।

इस मुद्दे पर अब 30 अमेरिकी सीनेटरों ने विदेश विभाग पर दबाव बनाते हुए F, M और J वीजा के प्रोसेसिंग में हो रही देरी का बना रहा है। इस फैसले ने डेमोक्रेटिक सांसदों और नागरिक अधिकार संगठनों में तीखी आलोचना पैदा कर दी है। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (डीएचएस) ने सोमवार को जारी नोटिस में बताया कि आईसीई होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस और एनफोर्समेंट रिमूवल ऑपरेशंस के अधिकारियों के लिए जनरेटेड लो आउटपुट वोल्टेज एमिटर यानी जीएलओवीई खरीदने जा रहा है।

बटन दबाते ही लगेगा 380 वोल्ट का करंट!

वाशिंगटन। अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (आईसीई) अपने अधिकारियों और एजेंटों के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देने वाले दस्तानों पर 2 करोड़ डॉलर तक खर्च करने की योजना

'ईरान रच रहा हत्या की साजिश'

वॉशिंगटन। पिछले महीने तुर्किए से निकलते समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने गुपचुप तरीके अपना विमान बदला था। अब खुलासा हुआ है कि ट्रंप ने ऐसा तब किया जब इजरायल ने चेतावनी दी थी कि ईरान उनकी हत्या की साजिश रच रहा है। अमेरिका के नेशनल पब्लिक रेडियो की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल ने अमेरिकी अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि एयर फोर्स वन पर ईरानी मिसाइलों से खतरा हो सकता है।

टाटा संस में चंद्रशेखरन की जगह ले सकते हैं नरेंद्रन

चेयरमैन की रेस में टाटा स्टील के एमडी सबसे आगे

नई दिल्ली, एजेंसी



टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के अचानक इस्तीफे के बाद नए उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हो गई है। सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ने आज 13 अगस्त को एक प्रस्ताव पास कर 5 सदस्यीय सिलेक्शन कमेटी गठित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इस पद की रेस में टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर टीवी नरेंद्रन का नाम सबसे आगे है। नरेंद्रन 1988 से टाटा ग्रुप से जुड़े हुए हैं। उनका पूरा करियर टाटा स्टील में ही रहा है।

चंद्रशेखरन ने भले ही इस्तीफा दे दिया हो लेकिन वे फरवरी 2027 तक टाटा संस के चेयरमैन पद पर बने रहेंगे। यानी वे अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। इस वजह से टाटा संस के पास नया प्रमुख को चुनने और उनके स्मूथ ट्रांजैक्शन की योजना बनाने के लिए लगभग 6 महीने का वक्त है। टाटा संस के नियमों के मुताबिक चेयरमैन के चयन के लिए 5 सदस्यों की एक खास कमेटी बनाई जाती है। नामों की स्क्रूटनी के बाद कमेटी उनका इंटरव्यू करती है। फिर टाटा संस बोर्ड को अंतिम नाम की सिफारिश की जाती है। मुश्किल दौर में शानदार परफॉर्मेंसः नरेंद्रन ने जब पद संभाला, तब टाटा स्टील भारी कर्ज, वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव और महंगे विदेशी अधिग्रहणों से जूझ रही थी। उन्होंने कर्ज कम करने, कैश फ्लो सुधारने और डोमेस्टिक पोजीशन मजबूत करने पर काम किया।

लाल किला धमाका अलकायदा ने कराया

यूएन की रिपोर्ट में दावा, एनआईए की जांच में भी यही निकला था, 11 मौतें हुई थीं

नई दिल्ली, एजेंसी

लाल किले के पास हुए धमाके में अलकायदा से जुड़े संगठन का हाथ था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की 38वीं रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। 10 नवंबर 2025 की शाम लाल किले के पास हुए इस धमाके में 11 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए थे।

रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) ने इस धमाके को अंजाम दिया। इसमें कहा गया है कि AQIS अब छोटे-छोटे सेल के जरिए काम कर रहा है और उसने अपना लॉजिस्टिक्स, फाइनेंशियल नेटवर्क भी तैयार कर लिया है।

इससे पहले आई UNSC की 37वीं रिपोर्ट में एक सदस्य देश ने इस हमले के पीछे जैश-ए-मोहम्मद (JeM) का हाथ बताया था। यानी इस हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की लगातार दो रिपोर्टों में दो अलग-अलग आतंकी संगठनों के नाम सामने आए हैं। हालांकि, NIA की चार्जशीट में दावा किया गया था कि आरोपी AQIS से जुड़े थे। UNSC की एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम की यह रिपोर्ट 10 अगस्त को जारी की गई। इसमें कहा गया है कि AQIS अब बिखरे हुए छोटे आतंकी संगठन की बजाय एक क्षेत्रीय आतंकी नेटवर्क के रूप में विकसित हो चुका है। संगठन ने अपना लॉजिस्टिक्स और फाइनेंशियल नेटवर्क तैयार कर लिया है और अब बड़े समूहों के बजाय छोटे-छोटे, अलग-अलग सेल के जरिए काम कर रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि AQIS बांग्लादेश में भी अपने आतंकी सेल बनाने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट में इसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया गया है।



रासायनिक और जैविक हथियार बनाने की कोशिश में जुटा अलकायदा

रिपोर्ट में कहा गया है कि अलकायदा और इस्लामिक स्टेट (ISIL/दाएश) लंबे समय से ऐसे जहरीले रासायनिक और जैविक हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे बड़ी संख्या में लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। हालांकि, अब तक वे इसमें पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि ऐसे हथियार बनाना बेहद मुश्किल काम है।

रिपोर्ट के मुताबिक, इन आतंकी संगठनों से जुड़े ऑनलाइन नेटवर्क पर अब भी ऐसे जहरीले पदार्थ बनाने के तरीके और जानकारी साझा की जा रही है।

फरवरी में ISIL की अंग्रेजी पत्रिका 'इनवेड' में बोटुलिनम टॉक्सिन और साइनाइड जैसे जहरीले पदार्थ तैयार करने से जुड़े निर्देश प्रकाशित किए गए थे।

10 नवंबर 2025 की शाम हुआ था धमाका

दिल्ली के लाल किला इलाके में 10 नवंबर 2025 की शाम जोरदार धमाका हुआ था। इससे आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए थे। कई दुकानों और इमारतों को भी नुकसान पहुंचा था। 11 लोगों की मौत हुई थी। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। शुरुआती जांच में ही जांच एजेंसियों को शक हो गया था कि यह हाई-इंटेंसिटी VBIED अटैक था। इस केस की गंभीरता को देखते हुए जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंप दी गई थी।

पत्रकारों पर तंज के लिए मशहूर थीं, कहा- अच्छी मां बनना चाहती हूं

ट्रम्प की वफादार कैरोलिन लेविट ने नौकरी छोड़ी

वॉशिंगटन डीसी, एजेंसी



अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में गिनी जाने वाली व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 28 साल की लेविट इस महीने के आखिर में व्हाइट हाउस छोड़ देंगी।

ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि लेविट अब अपने परिवार और दो छोटे बच्चों को ज्यादा समय देना चाहती हैं। हालांकि, वह ट्रम्प की बाहरी सलाहकार बनी रहेंगी और रिपब्लिकन पार्टी के लिए काम करती रहेंगी।

लेविट 27 साल की उम्र में अमेरिका के इतिहास की सबसे कम उम्र की व्हाइट हाउस प्रेस सचिव बनी थीं। मई में बेटी के जन्म के बाद वह कुछ समय के मातृत्व अवकाश पर गई थीं और कुछ दिन पहले काम पर लौटी थीं। उनका एक दो साल का बेटा भी है।

करीब 20 महीने तक कैरोलिन लेविट व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की सबसे भरोसेमंद प्रवक्ता रहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब भी ट्रम्प की नीतियों, फैसलों या विवादों पर मुश्किल सवाल पूछे जाते, तो उनका जवाब देने की जिम्मेदारी अक्सर लेविट ही संभालती थीं। उन्होंने कई बार ट्रम्प का आक्रामक तरीके से बचाव किया और मीडिया के सवालों का तीखे अंदाज में जवाब दिया। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पत्रकारों के साथ उनकी कई बार तीखी नोकझोंक हुई, जो सुर्खियों में रही। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सवाल पूछने वाले एक रिपोर्टर को 'वामपंथी सोच वाला' और 'पत्रकार के नाम पर कलंक' तक कह दिया था। इस बयान के बाद काफी विवाद हुआ।

डिलीवरी से ठीक पहले भी ड्यूटी निभाई

अप्रैल 2026 में जब व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान हुई गोलीबारी पर पूरी दुनिया की नजर थी, तब कैरोलिन लेविट ने अपना मातृत्व अवकाश शुरू करने के बजाय खुद कैमरे के सामने आकर ट्रम्प प्रशासन की पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया दी। इसके बाद ही वह मातृत्व अवकाश पर गईं।

मई 2026 में बेटी के जन्म के बाद करीब दो महीने छुट्टी पर रहीं, जुलाई में काम पर लौटीं और एक महीने बाद इस्तीफे का ऐलान कर दिया।



■ लेविट ने दिसंबर 2025 में अपनी गर्भावस्था की घोषणा की थी। तब वह पहली ऐसी व्हाइट हाउस प्रेस सचिव बनीं, जो पद पर रहते हुए गर्भवती बनी थीं।

आसमान में सूर्य-चंद्रमा का अद्भुत मिलन

यूरोप में दिखा सूर्य ग्रहण का दुर्लभ नजारा

लंदन, एजेंसी



यूके और यूरोप के आसमान में हाल ही में एक ऐतिहासिक खगोलीय नजारा देखा गया, जिसने लाखों लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पिछले लगभग तीन दशकों में क्षेत्र का सबसे शानदार माना जाने वाला यह दुर्लभ सूर्य ग्रहण जब अपने चरम पर पहुंचा, तो दिन के उजाले में भी शाम की धुंधलका छा गया।

विशेष रूप से यूके में स्थानीय समयानुसार, शाम 7:00 बजे के ठीक बाद इस आंशिक सूर्य ग्रहण का सबसे अद्भुत रूप देखने को मिला, जहां चंद्रमा ने सूर्य के 90 प्रतिशत से अधिक हिस्से को पूरी तरह ढक लिया था। ग्रहण की पूर्णता का पथ साइबेरिया (रूस) के उत्तरी सिरे से शुरू हुआ, आर्कटिक महासागर से होते हुए प्रारंभिक शाम में आइसलैंड पहुंचा। फिर यह दक्षिण की ओर यूके की तरफ मुड़ा। उत्तरी स्कॉटलैंड में स्थानीय समय के अनुसार करीब 6 बजे और इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर करीब 6:20 बजे आंशिक ग्रहण शुरू हुआ। मध्य और दक्षिणी इंग्लैंड तथा वेल्स के बड़े हिस्से में साफ आसमान ने दर्शकों को लगभग एक घंटे तक चंद्रमा के सूर्य पर गुजरने का अबाधित नजारा दिया। उत्तरी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड में बादल छाए रहे, फिर भी देशभर के ऐतिहासिक स्थलों पर भीड़ जुटी।

बढ़ोतरी : 1.33 लाख करोड़ के खर्चे का मांगा हिसाब, अमेरिका ने इस भारी सैन्य आवंटन पर अपनी गहरी चिंता जताई

पाकिस्तान के भारी-भरकम सैन्य बजट में बढ़ोतरी पर यूएस सख्त

वाशिंगटन, एजेंसी



■ पाकिस्तान के भारी-भरकम सैन्य बजट में बढ़ोतरी पर अमेरिका सख्त

गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे पाकिस्तान ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अपने रक्षा बजट में बड़ी बढ़ोतरी करते हुए इसे 1.33 लाख करोड़ रुपये घोषित किया है। यह भारी-भरकम राशि पाकिस्तान के कुल 6.38 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय बजट का लगभग 20.84 प्रतिशत हिस्सा है।

अपनी डगमगाती अर्थव्यवस्था के बावजूद सेना पर पानी की तरह पैसा बहाने की इस नीति ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को चौंका दिया है। विशेष रूप से अमेरिका ने इस भारी सैन्य आवंटन पर अपनी गहरी चिंता जताई है। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान पाकिस्तान के रक्षा बजट में 41 प्रतिशत की अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है। चालू वित्त वर्ष में हथियार, गोला-बारूद और नए सैन्य उपकरणों जैसे फिजिकल एसेट्स के लिए 31,480 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जो पिछले साल से 40 फीसदी अधिक है।

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के अनुसार, वर्ष 2021 से 2025 के बीच पाकिस्तान के हथियार आयात में 66 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। चिंताजनक बात यह है कि आयात किए गए कुल हथियारों में से 80 प्रतिशत आपूर्ति अकेले चीन द्वारा की गई है, जिससे पाकिस्तान दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया है।

पारदर्शिता पर उठे गंभीर सवाल

अमेरिकी विदेश विभाग की फिस्कल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2025 में पाकिस्तान के रक्षा खर्चों की निष्पक्षता और जवाबदेही पर कड़े सवाल खड़े किए गए हैं। इस रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि पाकिस्तान के सैन्य बजट पर न तो पर्याप्त संसदीय समीक्षा होती है और न ही किसी प्रकार की नागरिक निगरानी व्यवस्था उपलब्ध है।

अमेरिका ने पाकिस्तान सरकार से आग्रह किया है कि वह अपने सरकारी कर्ज, सार्वजनिक उपक्रमों की देनदारियों और रक्षा से जुड़े खर्चों की सटीक जानकारी समय पर सार्वजनिक करे।

मुस्लिम नाटो समझौते के तुरंत बाद अमेरिकी चेतावनी

अमेरिका की ओर से आई यह चेतावनी राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से भी बेहद अहम मानी जा रही है। हाल ही में 7 अगस्त को मक्का में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये के बीच एक त्रिपक्षीय रणनीतिक समझौता हुआ, जिसे मुस्लिम नाटो के रूप में देखा जा रहा है। इस समझौते में नाटो के अनुच्छेद-5 की तर्ज पर यह प्रावधान शामिल किया गया है कि किसी भी एक सदस्य देश पर हुआ हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। इस समझौते के ठीक पांच दिन बाद अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, जिसने पाकिस्तान के सैन्य इरादों पर निशाना साधा है।

माल्या- एसबीआई विवाद खत्म करें : बॉम्बे हाईकोर्ट

इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा

मुंबई, एजेंसी



बॉम्बे हाई कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या और बैंकों के बीच चल रहे कॉमर्शियल विवाद को अब खत्म करने की बात कही है। कोर्ट ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED से जांच की मौजूदा स्थिति और अटैच की गई संपत्तियों का ब्योरा भी मांगा है। जस्टिस मिलिंद जाधव की सिंगल जज बेंच ने माल्या की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर दोनों पक्ष इस विवाद को खत्म कर आगे नहीं बढ़ते हैं, तो इसका देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा और नकारात्मक असर पड़ेगा।

हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि लगभग एक दशक से चल रहे इस मामले को अब एक तार्किक अंत यानी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचना चाहिए। 70 साल के विजय माल्या ने याचिका दाखिल कर संपत्तियों को बैंकों को सौंपने के आदेश को अनुचित बताया था।

इस पर कोर्ट ने कहा कि कॉमर्शियल विवादों का समाधान अक्सर खुद विवादों के भीतर ही छिपा होता है। पक्षों को आपसी उलझन में रहने की बजाय व्यावहारिक समाधान यानी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए। साल 2020 में माल्या ने विशेष प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगुआई वाले बैंकों के कंसोर्टियम को ED द्वारा अटैच की गई उसकी संपत्तियों का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी।

तमसा संकेत
tamsa.newslko@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक विद्या देवी द्वारा कृष्णा डाइनेस्टी प्रिंटिंग प्रेस म0 न0 195 सेक्टर 6-बी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड लखनऊ-226 029 (उ0प्र0) से मुद्रित व प्रकाशित।

सम्पादक : विद्यादेवी

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा

समाचार पत्र में प्रकाशित लेख, राजनीतिक विश्लेषण, लेखकों के अपने विचार हैं। सम्पादक का इन विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं हैं।
मो0- 9415799533
R.N.I. NO. UPHIN/2021/83676